STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP)
(FY2017-20)

State – Chhattisgarh

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

TABLE OF CONTENTS

Checklist – Consolidated State Annual Action Plan of all ULBs (as per table 6.2) 3

Minutes of State High Powered Steering Committee (SHPSC) Meeting 5

Chapter 1: Project Background and Summary 10

1.1 AMRUT Mission 10

1.2 Thrust Areas & components under the Mission: 10

1.2.1 Water supply, 10

1.2.2 Sewerage facilities and septate management, 11

1.2.3 Storm Water Drainage 11

1.2.4 Urban Transport 11

1.2.5 Green Space & Park 11

1.2.6 Reforms management & support 11

1.2.7 Capacity Building 12

1.3 Mission Cities 12

1.4 Programme Management & Implementation Structure 13

1.4.1 National Level 13

1.4.2 State Level 13

1.4.3 City Level 14

1.5 Overview of Population and Investment 14

1.6 TECHNOLOGICAL INNOVATION 15

1.7 Financial Allocation 15

1.8 Project Fund 16

1.9 Fund sharing pattern for entire Mission 16

1.10 Sector wise project fund allocation/ requirement for the mission period (2015 – 2020) 17

1.11 Investment under the Mission 18

Chapter 2: Review of SAAPs 29

2.1 Project Cost at a glance: 29

2.2 Project Progress 32

2.3 Service Levels 41

2.4 Capacity Building 42
2.5 Reforms 45
2.6 Use of A&OE 45
2.7 Funds flow 46
2.8 Fund disbursements and CONDITIONS 48
Chapter 3: STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP) 50
3.1 Principles of Prioritization 56
3.2 Importance of O&M 58
3.3 Reform Implementation 60
3.4 Annual Capacity Building Plan 65
a. A&OE 68
b. Financing of Projects 69
Chapter 4: TABLES: 72

Report Submitted by: State Mission Director, Chhattisgarh
Date: *07/03/2017*

CHECKLIST – CONSOLIDATED STATE ANNUAL ACTION PLAN OF ALL ULBS (AS PER TABLE 6.2)

Sr. No	Points of Consideration	Yes/No	Give Details
1.	Have all the Cities prepared SLIP as per the suggested approach?	YES	SLIPs prepared and submitted by the cities as per the AMRUT guidelines and are in conformity with the National and State Priority i.e. providing universal coverage of water and sewerage/ septage in all the AMRUT cities.
2.	Has the SAAP prioritized cities for investment as per priority sector and gap assessment?	YES	SAAP has prioritized proposed investment across cities as per the principle of prioritization (para 7.2) of AMRUT. Distribution of investment is based on priority for providing 100% universal coverage in primary thrust sectors.
3.	Is the indicator wise summary of improvements proposed (both investments and management improvements) by State in place?	YES	Indicator wise summary of improvements proposed by the State is enclosed at Table 1.4 of SAAP.
4.	Have all the cities under Mission identified/done baseline assessments of service coverage indicators?	YES	SLB notification of all 9 cities has been carried out.
5.	Is the SAAP derived from an approach towards meeting Service Level Benchmarks agreed by Ministry for each Sector?	YES	SAAP has been prepared to meet Service Level Benchmarks as agreed by the MoUD.
6.	Is the investment proposed commensurate to the level of improvement envisaged in the indicator?	YES	The proposed investments commensurate to the Service Level improvement envisaged in the indicator.
7.	Are State Share and ULB share in line with proposed Mission approach?	YES	The share of the state government will be 40% in case of cities with population above 10 lakhs and 30% in case of cities with population up to 10 lakhs. ULB share will be 20% in case of cities with population more than 10 lakhs and 30% in case of cities with population up to 10 lakhs.
8.	Is there a need for additional resources and have state considered raising additional	YES	Efforts are being made to mobilize additional resources through 14th Finance Commission, External Sources etc.

	resources (State programs, aided projects, additional devolution to cities, 14th Finance Commission, external sources)?		
9.	Does State Annual Action Plan verify that the cities have undertaken financial projections to identify revenue requirements for O&M and repayments?	YES	The O&M of the projects proposed under the mission shall be reimbursed by the user-charges collected by the ULBs. The additional fund required for O&M and repayment shall be worked out in detail at the time of preparation of DPR.
10.	Has the State Annual Action Plan considered the resource mobilization capacity of each ULB to ensure that ULB share can be mobilized?	YES	Efforts are being made to mobilize maximum portion of ULB share through 14th Finance Commission Grant and any shortfall will be catered though providing loan to ULBs.
11.	Has the process of establishment of PDMC been initiated and completed?	YES	PDMC has been established.
12.	Has a roadmap been prepared to realize the resource potential of the ULB?	YES	The resource potential of each city has been considered while preparing SAAP.
13.	Is the implementation plan for projects and reforms in place (Timelines and yearly milestones)?	YES	Implementation of reforms shall be as per timeline set in the mission guidelines.
14.	Has the prioritization of projects in ULBs been done in accordance with para 7.2 of the guidelines?	YES	Projects have been prioritized in accordance with Para 7.2 of the guidelines with main consideration of potential smart city, universal coverage principle, resource capability of respective ULB etc.

(Niranjan Das)
Mission Director (AMRUT)
Chhattisgarh

MINUTES OF STATE HIGH POWERED STEERING COMMITTEE (SHPSC) MEETING

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

–:: कार्यवाही विवरण ::–

मुख्य सचिव महो. की अध्यक्षता में आहूत अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की तृतीय बैठक दिनांक 21.02.2017

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित अमृत मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय हाईपावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की तृतीय बैठक दिनांक 21.02.2017 को सायं 4:00 बजे मंत्रालय महानदी भवन स्थित मुख्य सचिव के कार्यालयीन प्रतिकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण सम्मिलित हुए :–

1.	श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	– अध्यक्ष
2.	श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग	– सदस्य
3.	श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग	– सदस्य
4.	श्री संजय शुक्ला, सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण	– सदस्य
5.	श्रीमती शहला निगार, सचिव, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां. विभाग	– सदस्य
6.	डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नग.प्रशा. एवं वि.वि.	– सदस्य
7.	श्री अभिनव अग्रवाल, संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूडा	– सदस्य सचिव
8.	श्री रजत बंसल, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर	– विशेष आमंत्रित
9.	श्री अश्विनी देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगांव	– विशेष आमंत्रित
10.	श्री सौमिल रंजन चौबे, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर	– विशेष आमंत्रित
11.	श्री लवकुश सिंगरौल, आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर	– विशेष आमंत्रित
12.	श्री एस.एन. दास, सहायक अभियंता नगर पालिक निगम जगदलपुर	– विशेष आमंत्रित

निर्णय क्र. 01 :– राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी (SHPSC) की द्वितीय बैठक दिनांक 27.05.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में – समिति द्वारा SHPSC की द्वितीय बैठक दिनांक 27.05.2016 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

निर्णय क्र. 02 :– वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित रिफार्म क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से पुरस्कार के रूप में प्राप्त प्रोत्साहन राशि रू. 13.00 करोड़ के संबंध में – वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित रिफार्म क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से पुरस्कार के रूप में प्राप्त प्रोत्साहन राशि रू. 13.00 करोड़ के संबंध में चर्चा उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

1

निर्णय क्र. 03 :– मिशन अमृत अंतर्गत स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुमोदन के संबंध में – मिशन अमृत अंतर्गत स्टेट सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी का समिति द्वारा चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्र. 04 :– वॉटर रिसाईकिल एण्ड रियूज़ पॉलिसी (Water Recycle & Reuse Policy) के अनुमोदन के संबंध में – वॉटर रिसाईकिल एण्ड रियूज पॉलिसी में रिसाईकिल वॉटर का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से किये जाने का प्रावधान सम्मिलित करते हुए, समिति द्वारा चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्र. 05 :– मिशन अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्र. K-16011/76/2016 **दि. 26.09.16 के परिपेक्ष्य में मिशन के दिशा–निर्देश अनुसार विद्यमान जल प्रदाय एवं सीवरेज व्यवस्था में संलग्न पावर पंपों इत्यादि का एनर्जी आडिट भारत सरकार द्वारा चयनित फर्म एनर्जी एफिसियेंट सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) कंपनी से किये गए एमओयू के संबंध में –** समिति प्रकरण की सूचना से अवगत हुई एवं निर्देशित किया गया कि, राज्य शासन की ओर से सूडा तथा ईईएसएल के मध्य कारित एमओयू में पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से आई.जी.ई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु एजेंसी के चयन एवं भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा किये जाने संबंधी आवश्यक संशोधन करने की अनुमति तथा ईईएसएल को निर्देशित करने हेतु भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय को लेख किया जावे।

निर्णय क्र. 06 :– मिशन शहरों के आयुक्तों को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में – मिशन शहरों के आयुक्तों को वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में समिति द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

निर्णय क्र. 07 :– कोरबा जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग से सर्वेश्वर एनिकट निर्माण की लागत में वृद्धि के कारण योजना पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में – समिति द्वारा चर्चा उपरान्त सर्वेश्वर एनिकट निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रू. 5323.35 लाख को सम्मिलित करते हुए, कोरबा जल प्रदाय योजना फेस–।। हेतु अनुमानित लागत राशि रू. 22998.62 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। **साथ ही निर्देशित किया गया कि, कार्योत्तर पुष्टि हेतु प्रकरण प्रोजेक्ट फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग कमेटी (पीएफआईसी) में भी शीघ्र प्रस्तुत किया जावे।**

निर्णय क्र. 08 :– मिशन अंतर्गत, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की अद्यतन प्रगति की समीक्षा (पावरपाईन्ट प्रस्तुति द्वारा) – डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की अद्यतन प्रगति की समीक्षा पावरपाईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से की गई, जिससे समिति अवगत हुई।

निर्णय क्र. 09 :– मिशन अंतर्गत, वर्ष 2017–18 के स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) के अनुमोदन के संबंध में – डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष मिशन अमृत का वर्ष 2017–18 का निम्नांकित स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) पावरपाईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से (निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित) प्रस्तुत किया गया –

Master SAAP (FY - 2015-2020) (Amount in Crore)					
S.No.	Name of ULB	Project cost in Cr.	Year Wise Financial Statement		
			Water Supply	Sewerage/ Septage	Parks and Green Spaces
1	Raipur	525.40	186.75	330.65	7.00
2	Bilaspur	352.55	304.36	21.79	6.00
3	Durg	84.58	145.00	15.00	3.20
4	Bhilai	279.19	242.73	20.00	4.00
5	Rajnandgaon	246.18	223.68	14.00	4.00
6	Korba	286.99	229.99	18.00	4.00
7	Raigarh	149.58	148.00	10.00	3.20
8	Ambikapur	129.28	106.98	8.00	4.00
9	Jagdalpur	139.00	119.42	10.00	3.00
Total		**2192.75**	**1706.91**	**447.44**	**38.40**

Breakup of Share:- ALL SECTORS														
S. No.	Name of ULB	Project cost in Cr.	Year Wise Financial Statement											
			2015-16				2016-17				2017-18			
			CS	SS	ULB	Total	CS	SS	ULB	Total	CS	SS	ULB	Total
1	Raipur	524.40	20.47	24.56	16.37	61.40	125.19	149.05	99.36	373.60	29.91	35.70	23.80	89.4
2	Bilaspur	332.15	52.62	31.57	21.05	105.23	42.52	25.51	17.01	85.05	70.94	42.56	28.38	141.8
3	Durg	163.20	25.77	15.46	10.31	51.53	3.80	2.28	1.52	7.60	52.04	31.22	20.81	104.0
4	Bhilai	266.73	48.95	29.37	19.58	97.90	49.35	29.61	19.74	98.69	35.07	21.04	14.03	70.1
5	Rajnandgaon	241.68	19.90	11.94	7.96	39.80	14.33	8.60	5.73	28.66	86.61	51.97	34.64	173.2
6	Korba	251.99	42.99	25.79	17.20	85.98	42.40	25.44	16.96	84.79	40.61	24.37	16.24	81.2
7	Raigarh	161.20	21.51	12.90	8.60	43.01	16.94	10.16	6.77	33.87	42.16	25.30	16.86	84.3
8	Ambikapur	118.98	26.51	15.91	10.60	53.02	0.86	0.52	0.34	1.72	32.12	19.27	12.85	64.2
9	Jagdalpur	132.42	17.77	10.66	7.11	35.53	13.20	7.92	5.28	26.39	35.25	21.15	14.10	70.5
	Total	2192.75	276.47	178.16	118.77	573.40	308.57	259.07	172.72	740.37	424.70	272.57	181.71	878.9

चर्चा उपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से मिशन अमृत के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के उपरोक्त स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (SAAP) का सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए, भारत सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय क्र. 10 :– मिशन अंतर्गत तैयार जल प्रदाय योजनाओं के डीपीआर की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में :–

अ. जल प्रदाय योजना अंबिकापुर
ब. जल प्रदाय योजना बिलासपुर
स. जल प्रदाय योजना जगदलपुर
द. जल प्रदाय योजना राजनांदगांव
ई. जल प्रदाय योजना रायपुर

समिति द्वारा चर्चा उपरान्त, मिशन अमृत के अंतर्गत (अ) जल प्रदाय योजना अंबिकापुर हेतु अनुमानित लागत 10697.98 लाख (ब) जल प्रदाय योजना बिलासपुर हेतु अनुमानित लागत 21262.29 लाख (स) जल प्रदाय योजना जगदलपुर हेतु अनुमानित लागत 11941.68 लाख (द) जल प्रदाय योजना राजनांदगांव हेतु अनुमानित लागत 22367.51 लाख (ई) जल प्रदाय योजना रायपुर हेतु अनुमानित लागत 18675.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। **साथ ही निर्देशित किया गया कि, उपरोक्त प्रकरणों की कार्योत्तर पुष्टि हेतु प्रकरण पीएफआईसी की बैठक में शीघ्र प्रस्तुत किया जावे तथा नगर निगम रायपुर की जल प्रदाय योजना में स्काडा साफ्टवेयर के परिपेक्ष्य में व्ही.एन.आई.टी. नागपुर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकता होने की स्थिति में प्री–बिड स्तर पर निविदा की PAC तथा परियोजना लागत में तदानुसार आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु मिशन डायेरक्टर (अमृत) को अधिकृत किया गया।**

निर्णय क्र. 11 :– मिशन अंतर्गत राजनांदगांव शहर की सेप्टेज मैनेजमेंट योजना के डीपीआर की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में – समिति द्वारा चर्चा उपरान्त राजनांदगांव शहर की सेप्टेज मैनेजमेंट योजना लागत राशि 1178.00 लाख के डीपीआर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

अन्त में समिति की आगामी समस्त बैठकों में सचिव, जल संसाधन विभाग को विशेष रूप से आमंत्रित करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा प्रदान किये गए। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त निर्देशानुसार बैठक समाप्त घोषित की गई।

(मुख्य सचिव सह अध्यक्ष एचपीएससी द्वारा अनुमोदित)

06/03/17

(डॉ. रोहित यादव)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

4

पृ.क्रमांक/09/सूडा/2016/3349 नया रायपुर, दिनांक :06/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग।
5. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
6. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग।
7. संयुक्त सचिव (मिशन अमृत) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. संयुक्त सचिव (यूडी) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
11. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़।
12. आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा एवं जगदलपुर।
13. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नया रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
14. रिकार्ड फाईल।

06/03/17

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

5

CHAPTER 1: PROJECT BACKGROUND AND SUMMARY

1.1 AMRUT MISSION

The Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India launched the programme Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) on 25th June, 2015 to augment infrastructure in urban areas in order to improve quality of life, especially the poor and disadvantaged. The programme is multi-sectoral in its focus and aims to cover basic municipal services such as water supply, sewerage, septage management, urban transport, etc. The Mission intends to adopt a multipronged cross sectoral strategy of Non-Motorized Transport (NMT), developing green breathing spaces for the urban areas and adoption of innovative governance practices and technologies.

The focus of the programme has been very clearly enumerated as an inclusive programme wherein access to potable drinking water and management of waste water is defined as principle importance and takes precedence in the implementation strategy.

The AMRUT focuses on achieving universal coverage of all basic essential municipal services within the Mission timeline.

1.2 THRUST AREAS & COMPONENTS UNDER THE MISSION:

The purpose of AMRUT Mission is to:

a. Ensure that every household has access to a tap with assured supply of water and a sewerage connection;
b. Increase the amenity value of cities by developing greenery and well maintained open spaces (e.g. parks); and
c. Reduce pollution by switching to public transport or constructing facilities for non-motorized transport (e.g. walking and cycling). Therefore, the Mission will focus on the following Thrust Areas:

1.2.1 Water supply,

i. Water supply systems including augmentation of existing water supply, water treatment plants and universal metering.
ii. Rehabilitation of old water supply systems, including treatment plants.
iii. Rejuvenation of water bodies specifically for drinking water supply and recharging of ground water.
iv. Special water supply arrangement for difficult areas, hill and coastal cities, including those having water quality problems (e.g. arsenic, fluoride)

1.2.2 Sewerage facilities and septate management,

i. Decentralized, networked underground sewerage systems, including augmentation of existing sewerage systems and sewage treatment plants.
ii. Rehabilitation of old sewerage system and treatment plants.
iii. Recycling of water for beneficial purposes and reuse of wastewater.

1.2.3 Storm Water Drainage

i. Construction and improvement of drains and storm water drains in order to reduce and eliminate flooding.

1.2.4 Urban Transport

i. Ferry vessels for inland waterways (excluding port/bay infrastructure) and buses.
ii. Footpaths/walkways, sidewalks, foot over-bridges and facilities for non-motorized transport (e.g. bicycles).
iii. Multi-level parking.
iv. Bus Rapid Transit System (BRTS).

1.2.5 Green Space & Park

i. Development of green space and parks with special provision for child-friendly components.

1.2.6 Reforms management & support

i. Support structures, activities and funding support for reform implementation.
ii. Independent Reform monitoring agencies.

1.2.7 Capacity Building

i. This has two components- individual and institutional capacity building.

Besides the above sector focused projects, the State Governments and cities will also have to implement 11 reforms including e-Governance, constitution of municipal cadre, augmentation double entry accrual-based accounting system, appropriate city development plan, devolution of finances and functions, review of building bye laws, improvement in revenues, set up state-level financial intermediary, energy and water audits and Swachch Bharat Mission.

1.3 MISSION CITIES

The Government of Chhattisgarh has selected the following 9 Mission cities for development under AMRUT Mission.

Sr. No	City	Population (in lakhs)
1	Raipur Municipal Corporation	10.48
2	Bhilai Municipal Corporation	6.25
3	Korba Municipal Corporation	3.63
4	Bilaspur Municipal Corporation	3.49
5	Durg Municipal Corporation	2.67
6	Raigarh Municipal Corporation	1.66
7	Rajnandgaon Municipal Corporation	1.63
8	Ambikapur Municipal Corporation	1.25
9	Jagdalpur Municipal Corporation	1.25
Total population		32.31
Total Urban population of Chhattisgarh		59.37
Percentage urban population in State covered under AMRUT Mission		54%

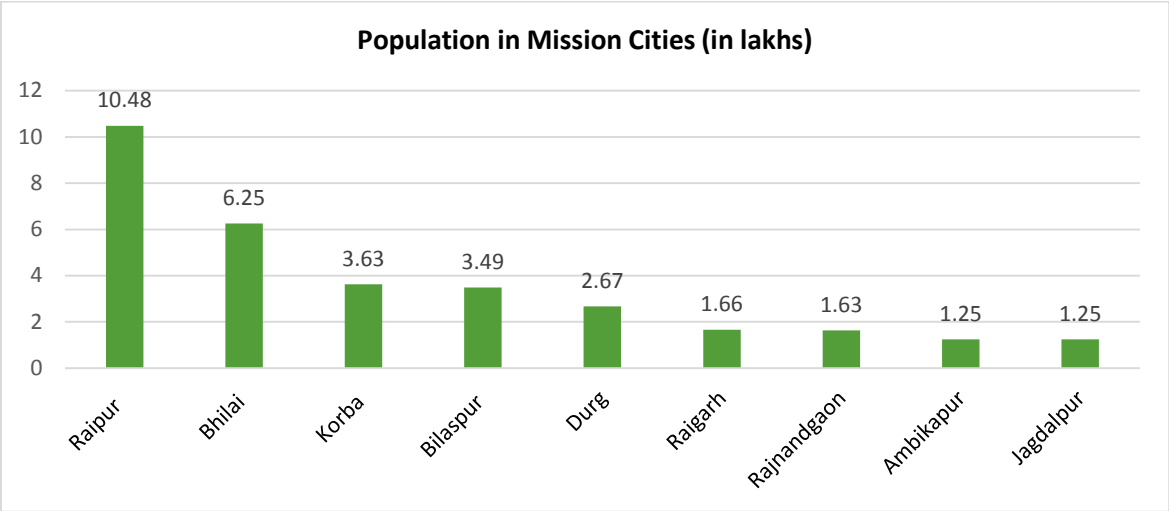

1.4 PROGRAMME MANAGEMENT & IMPLEMENTATION STRUCTURE

1.4.1 National Level

❖ Apex Committee (AC):

An Apex Committee (AC), chaired by the Secretary, MoUD and comprising representatives of related Ministries and organizations will approve the projects and supervise the Mission.

1.4.2 State Level

❖ State Level High Powered Committee (SHPSC):

As mandated by the AMRUT Guidelines, Government of Chhattisgarh has constituted State Level High Powered Committee (SHPSC) under the Chairmanship of Chief Secretary, GoCG vide Government Order No. F/5-19/2015/18 Dated 17-08-2015, Raipur.

At the Government of Chhattisgarh level, the Mission management scheme is presented as follows:

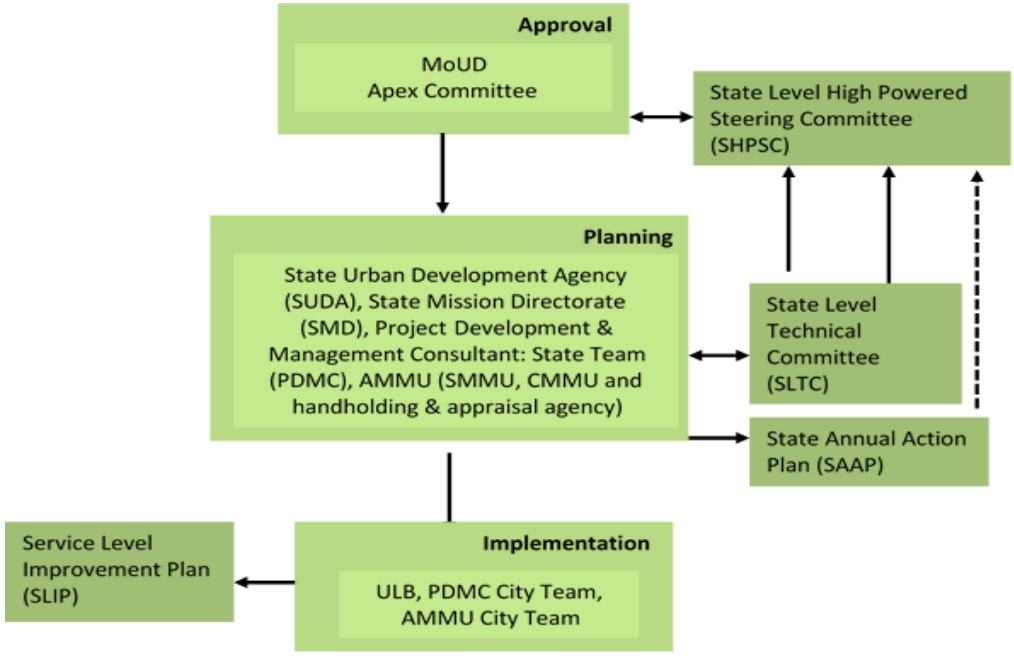

1.4.3 City Level

- Projects is being executed at City Level by the ULBs and parastatal agencies with the support of City Mission Management Units (CMMUs) & Programme Implementation Units (PIUs).
- Independent Review and Monitoring Agency External/ Third Party Agency, Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) is being appointed by MoUD to review the progress of projects and implementation of reforms, periodically.
- District Level Review and Monitoring Committee: a District Level Review and Monitoring Committee (DLRMC) will be constituted and Member(s) of Parliament will be the Co-chairperson with the District Collector. The DLRMC will monitor and review the implementation of the AMRUT projects.

1.5 OVERVIEW OF POPULATION AND INVESTMENT

The figures below indicate population of respective Mission Cities and their comparative investments envisaged under the Mission. As can be observed, investments are mostly in line with the population levels and variations are accounted for by the difference in service levels among different ULBs.

Population and Investment of Mission Cities

Sr. No	Name of ULB	Urban Population in lakhs (Census 2011)	Percentage of Investment under Mission
1	**Raipur**	10.48	23.92%
2	**Bilaspur**	3.49	15.15%
3	**Durg**	2.67	7.44%
4	**Bhilai**	6.25	12.16%
5	**Rajnandgaon**	1.63	11.02%
6	**Korba**	3.63	11.49%
7	**Raigarh**	1.66	7.35%
8	**Ambikapur**	1.25	5.43%
9	**Jagdalpur**	1.25	6.04%

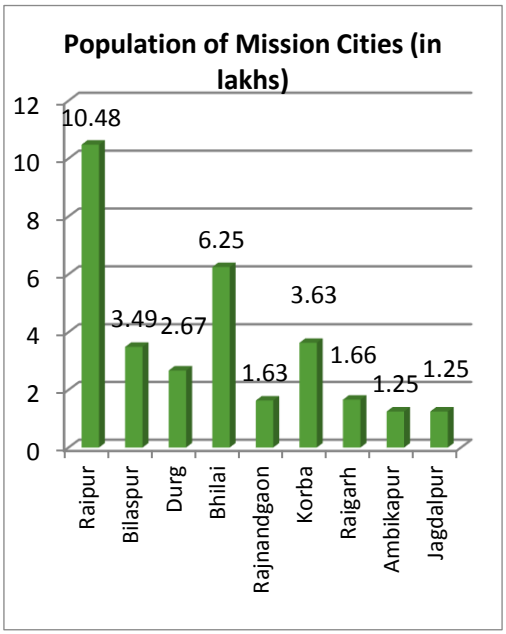

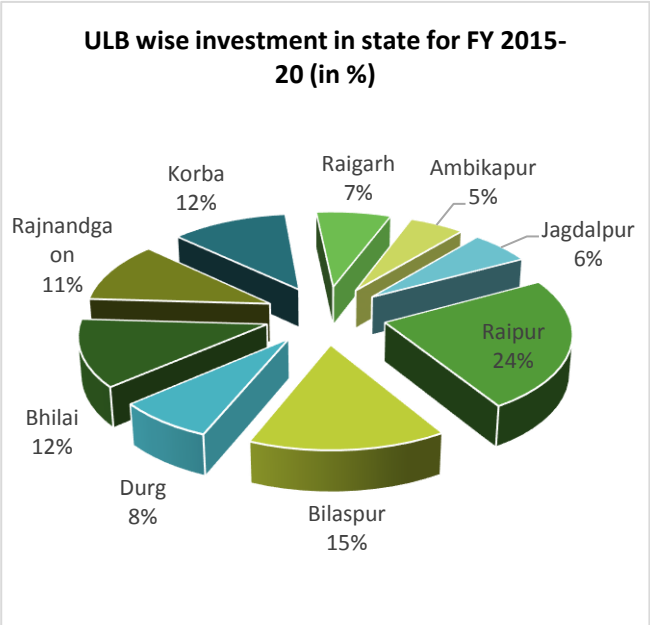

1.6 TECHNOLOGICAL INNOVATION

One of the most important components of the AMRUT schemes, as highlighted in the guidelines is technological innovations through minimum financial implications, which are replicable as well as scalable. In line of which following innovations has been adopted in the projects taken under the mission: -

a) **Application of PLC and SCADA:** Extensive application of PLC and SCADA has been adopted in the projects for better operation and maintenance practices and for optimum use of available resources.

b) **Application of Hydraulically Operated Diaphragm Valves:** Application of Hydraulically operated diaphragm type valves to control flow and pressure along with OHSR management. Use of such valves will substantially decrease the O&M charges and required number of Manpower is also very less.

c) **GIS Mapping:** GIS mapping of all the assets, which will help in reducing NRW and improve record keeping for O & M and future planning.

1.7 FINANCIAL ALLOCATION

Since the AMRUT is being operated as a Centrally Sponsored Scheme, the funds for the mission consists the following four parts:

i. Project fund - 80% of the annual budgetary allocation.
ii. Incentive for Reforms - 10% of the annual budgetary allocation.
iii. State funds for Administrative & Office Expenses (A&OE) - 8% of the annual budgetary allocation
iv. MoUD funds for Administrative & Office Expenses (A&OE) - 2% of the annual budgetary allocation.

1.8 PROJECT FUND

Govt. of India, vide DO Letter No. K-14012/95/2015-AMRUT-I, Dated 6th June, 2016, has allocated Rs. 1009.74 crores as total central assistance to the State of Chhattisgarh for entire mission period. SAAP-I & SAAP-II accounts for total of Rs 585.04 crores of ACA, hence SAAP-III is prepared for balance amount of Rs. 424.70 Crore to utilize full central assistance of Rs 1009.74Crore. Table below shows the allocated as well as the sanctioned amount for each SAAP: -

SAAP No	Amount of Central Assistance Allocated	Amount of Central Assistance Sanctioned	Deduction/ Adjustment
SAAP-I	276.47	276.47	0.00
SAAP-II	336.00	308.57	(-) 27.43
SAAP-III	397.27	424.70	(+)27.43
Total	1009.74	1009.74	0.00

To avail this whole central assistance of Rs.1009.74 crores, the SAAP for the entire balance three years has been prepared for Rs.424.70 crores including State & ULB share of Rs. 272.57Cr. & 181.71Cr. respectively.

1.9 FUND SHARING PATTERN FOR ENTIRE MISSION

Fund Sharing Pattern for the entire Mission (in Cr.)

Centre	State	ULBs	Total allocation
1009.74	709.81	473.20	2192.75

Fund Sharing Pattern for remaining mission period (2017-18, 2018-19 & 2019-20) (in Cr.)

Centre	State	ULBs	Total allocation
424.70	272.57	181.71	878.99

Fund Sharing Pattern for FY 2015- 16 (in Cr.)

Centre	State	ULBs	Total allocation
276.47	178.16	118.77	573.40

Fund Sharing Pattern for FY 2016 - 17 (in Cr.)

Centre	State	ULBs	Total allocation
308.57	259.07	172.72	740.365

1.10 SECTOR WISE PROJECT FUND ALLOCATION/ REQUIREMENT FOR THE MISSION PERIOD (2015 – 2020)

Sectors	2015 - 16	2016 - 17	Remaining Mission Period (2017-18, 2018-19 & 2019-20)	Total (Rs. In cr.)
Water supply	440.59	400.53	865.80	1706.91
Sewerage / Septage	122.79	320.65	4.00	447.44
Green Space & Parks	10.02	19.19	9.19	38.40
Total	573.40	740.37	878.99	2192.75

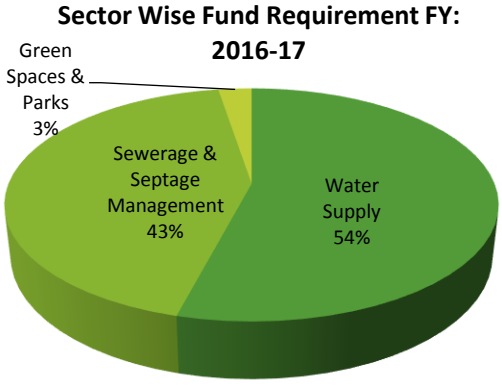

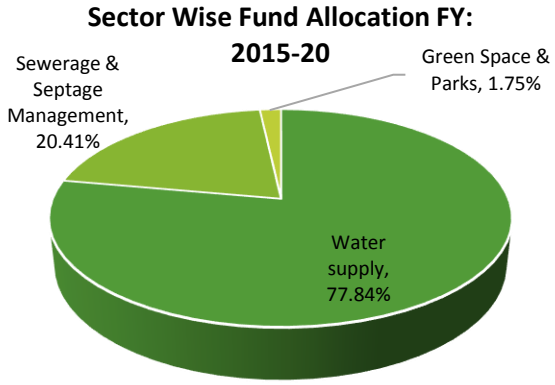

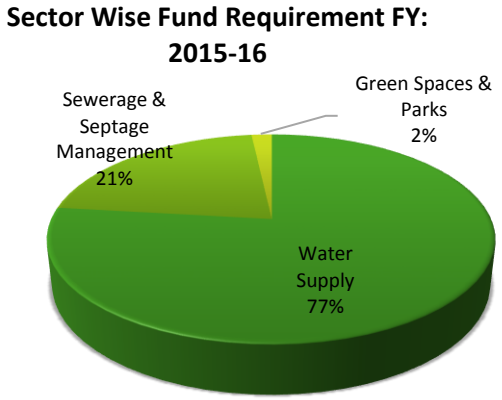

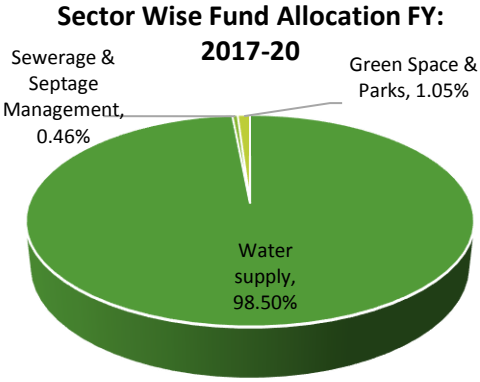

1.11 INVESTMENT UNDER THE MISSION

Financing is an important aspect of SAAP, since a minimum of 20% of the total project cost has to borne by the State Government. Considering the huge gap between available resources and requirement for achieving universal coverage, multi-pronged revenue enhancement options must be explored prior to which all municipal revenue sources must be inventoried and required regulatory framework instituted. The PDMC team will help identify appropriate PPP options and other sources of funding for the State share and also assist in formulating the state as well the ULB share in the funding.

Table 1.1: Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT: 2015-2020 (Amount in Cr.)

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	**Raipur**	186.75	330.65	7.00	524.40
2	**Bilaspur**	304.36	21.79	6.00	332.15
3	**Durg**	145.00	15.00	3.20	163.20
4	**Bhilai**	242.73	20.00	4.00	266.73
5	**Rajnandgaon**	223.68	14.00	4.00	241.68
6	**Korba**	229.99	18.00	4.00	251.99
7	**Raigarh**	148.00	10.00	3.20	161.20
8	**Ambikapur**	106.98	8.00	4.00	118.98
9	**Jagdalpur**	119.42	10.00	3.00	132.42
TOTAL		**1706.91**	**447.44**	**38.40**	**2192.75**
Total Project Investment					**2192.75**
A&OE					**80.78**
Grand Total					**2273.53**

NOTE: A&OE has been calculated as 8% of total central allocation (Rs. 1009.74) for mission period.

Table 1.1(a): Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT FY: 2017-20 (Amount in Cr.)

Total Central funds allocated to State	Allocation of Central funds for A&OE	Allocation of funds for AMRUT (Central share)	Central Allocation	State/ULB Share	Total AMRUT annual size (cols.4+5)
175.54	33.98	141.57	424.70	454.28	878.99

Table1.2.1: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern (Amount in cr.) FY-2015-2020

Sr. No.	Sector	No. of Projects*	Centre	State	ULB	Total
1	Water Supply	27	822.33	530.75	353.83	1706.91
2	Sewerage and Septage Management	12	168.61	167.30	111.53	447.44
3	Others (Green Spaces & Parks)	45	18.80	11.76	7.84	38.40
	Total	**84**	**1009.74**	**709.81**	**473.20**	**2192.75**
Note: No of projects may vary as per implementation suitability.						

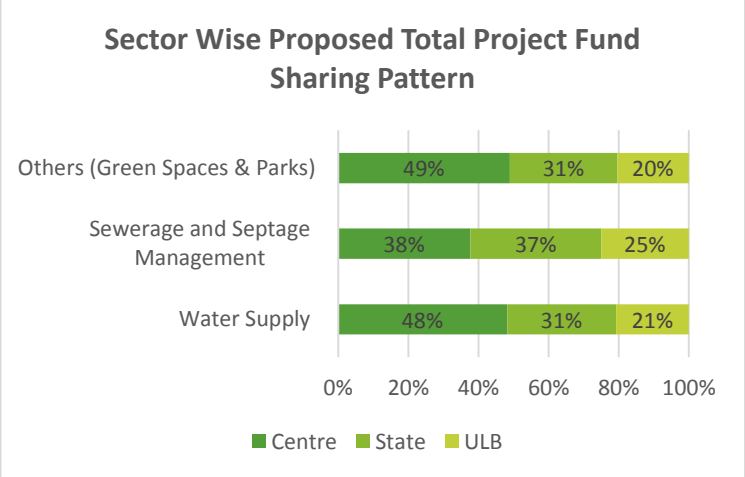

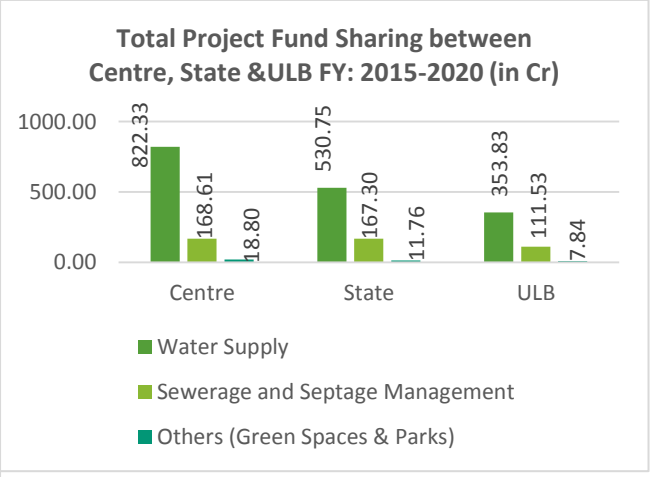

Table 1.2.2: Abstract Break –up of Total Fund Sharing Pattern (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Sector	Centre	State			ULB			Convergence	Others	Total
		Mission	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
1	**Water Supply**	822.33	-	530.75	530.75	353.83	-	353.83	-	-	**1706.91**
2	**Sewerage and Septage Management**	168.61	-	167.30	167.30	111.53	-	111.53	-	-	**447.44**
3	**Others (Green Spaces & Parks)**	18.80	-	11.76	11.76	7.84	-	7.84	-	-	**38.40**
Total		**1009.74**	-	**709.81**	**709.81**	**473.20**	-	**473.20**	-	-	**2192.75**

Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New For the Financial Year 2016-2017

Sr. No	Sector	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year (2015 - 2016 & 2016-17)							Proposed Spending during remaining Mission Period (2017 - 2020)							Balance Carry Forward for Next Financial Years						
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total
1	**Water Supply**	1706.91	404.22	0.0	262.13	262.13	0.0	174.76	174.76	418.11	0.0	268.61	268.61	0.0	179.08	179.08	-	-	-	-	-	-	-
2	**Sewerage and Septage**	447.44	166.61	0.0	166.10	166.10	0.0	110.73	110.73	2.00	0.0	1.20	1.20	0.0	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	-
3	**Others (Green Spaces & Parks)**	38.40	14.21	0.0	9.00	9.00	0.0	6.00	6.00	4.60	0.0	2.76	2.76	0.0	1.84	1.84	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		**2192.75**	**585.04**	**0.00**	**437.23**	**437.23**	**0.00**	**291.49**	**291.49**	**424.70**	**0.00**	**272.57**	**272.57**	**0.00**	**181.71**	**181.71**	-	-	-	-	-	-	-

Table 1.4: Abstract-Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Sector	Total Project Cost (in cr.)	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)				
				FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
Water Supply	**1706.91**	1. Household level coverage of direct water supply connections	**45.12**	-	-	-	**78.00**	**100.0**
		2. Per capita quantum of water supplied	**98.16**	-	-	-	**120.00**	**135.00**
		3. Quality of water supplied	**81.14**	-	-	-	**97.40**	**100.00**
Sewerage and Septage Management	**447.44**	4. Coverage of latrines (individual or community)	**69.92**	-	**95.20**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
		5. Coverage of sewerage network services	**4.67**	-	**6.69**	**33.50**	**78.80**	**100.00**
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	**6.67**	-	**7.30**	**40.30**	**85.70**	**100.00**
		7. Efficiency in treatment	**8.33**	-	-	**26.89**	**87.34**	**100.00**
Others (Green Spaces & Parks)	**38.40**	**No SLB study of parks and green spaces has been conducted yet. However at least one park in each mission city will be developed every year.**						

Table 3.2: SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	186.75	330.65	7.00	524.40
2	Bilaspur	304.36	21.79	6.00	332.15
3	Durg	145.00	15.00	3.20	163.20
4	Bhilai	242.73	20.00	4.00	266.73
5	Rajnandgaon	223.68	14.00	4.00	241.68
6	Korba	229.99	18.00	4.00	251.99
7	Raigarh	148.00	10.00	3.20	161.20
8	Ambikapur	106.98	8.00	4.00	118.98
9	Jagdalpur	119.42	10.00	3.00	132.42
	TOTAL	1706.91	447.44	38.40	2192.75
Total Project Investments					2192.75
A&OE (8% of Rs 1009.74 Cr. i.e. total allocation of central assistance for entire mission period)					80.78
Grand Total					2273.53

Table 3.2(a): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2016

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	10.00	2.40	61.40
2	Bilaspur	81.84	21.79	1.60	105.23
3	Durg	35.67	15.00	0.86	51.53
4	Bhilai	77.04	20.00	0.86	97.90
5	Rajnandgaon	26.94	12.00	0.86	39.80
6	Korba	67.12	18.00	0.86	85.98
7	Raigarh	32.15	10.00	0.86	43.01
8	Ambikapur	46.16	6.00	0.86	53.02
9	Jagdalpur	24.67	10.00	0.86	35.53
	TOTAL	440.59	122.79	10.02	573.40
Total Project Investments					573.40
A&OE					8.98
Grand Total					582.38

Table 3.2(b): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2016-2017

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	320.65	3.95	373.60
2	Bilaspur	81.85	0.00	3.20	85.05
3	Durg	5.88	0.00	1.72	7.60
4	Bhilai	96.97	0.00	1.72	98.69
5	Rajnandgaon	26.94	0.00	1.72	28.66
6	Korba	83.07	0.00	1.72	84.89
7	Raigarh	32.15	0.00	1.72	33.87
8	Ambikapur	0.00	0.00	1.72	1.72
9	Jagdalpur	24.67	0.00	1.72	26.39
TOTAL		400.53	320.65	19.19	740.37
Total Project Investments					740.37
A&OE					8.96
Grand Total					749.33

Table 3.2(c): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2017-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply		Sewerage and Septage Management		Others (Green Spaces & Parks)		Total	
		Amount	No of projects	Amount	No of projects	Amount	No of projects	Amount	No of projects
1	Raipur	88.75	1	0.00	-	0.65	3	89.40	4
2	Bilaspur	140.68	2	0.00	-	1.20	3	141.88	5
3	Durg	103.45	1	0.00	-	0.62	3	104.07	4
4	Bhilai	68.72	1	0.00	-	1.42	3	70.14	4
5	Rajnandgaon	169.80	1	2.00	1	1.42	3	173.22	5
6	Korba	79.80	1	0.00	-	1.42	3	81.22	4
7	Raigarh	83.70	1	0.00	-	0.62	3	84.32	4
8	Ambikapur	60.82	1	2.00	1	1.42	3	64.24	5
9	Jagdalpur	70.08	1	0.00	-	0.42	3	70.50	4
	TOTAL	865.80	10	4.00	2	9.19	27	878.99	39
Total Project Investments								878.99	
A&OE (80.78-8.98-8.96)								62.84	
Grand Total								941.83	

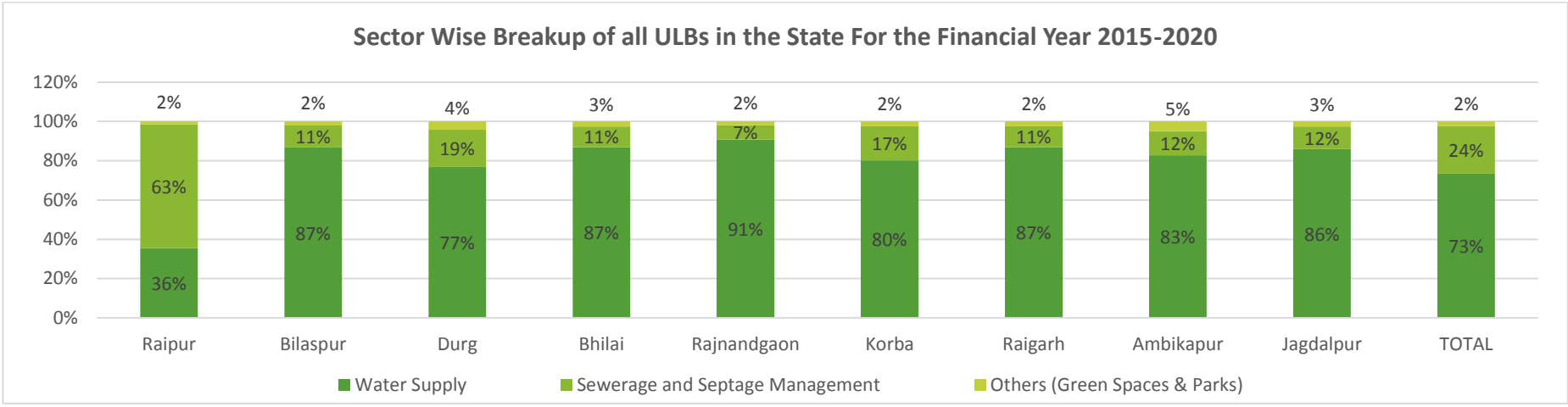
Sector Wise Breakup of all ULBs in the State For the Financial Year 2015-2020
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2%
63%
36%
2%
11%
87%
4%
19%
77%
3%
11%
87%
2%
7%
91%
2%
17%
80%
2%
11%
87%
5%
12%
83%
3%
12%
86%
2%
24%
73%
Raipur
Bilaspur
Durg
Bhilai
Rajnandgaon
Korba
Raigarh
Ambikapur
Jagdalpur
TOTAL
Water Supply
Sewerage and Septage Management
Others (Green Spaces & Parks)

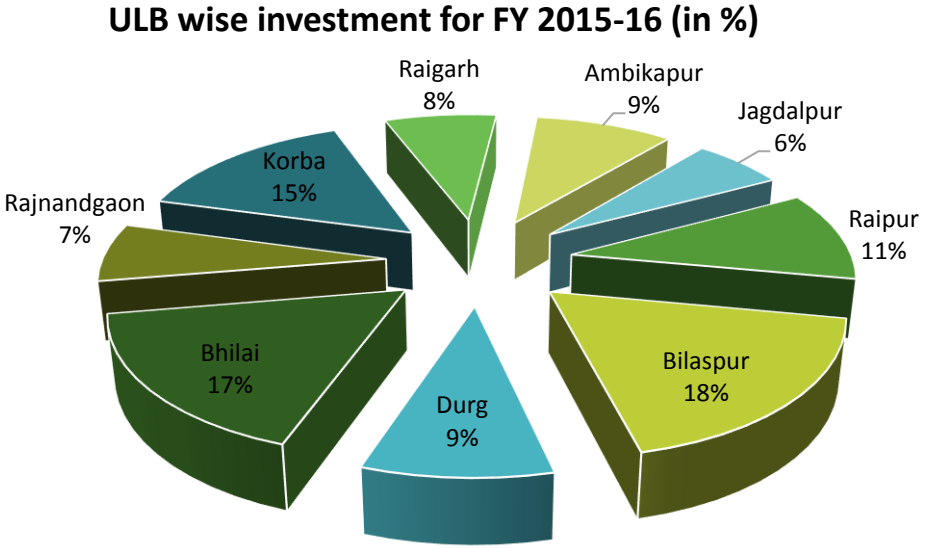
ULB wise investment for FY 2015-16 (in %)
Raigarh 8%
Ambikapur 9%
Jagdalpur 6%
Korba 15%
Rajnandgaon 7%
Raipur 11%
Bhilai 17%
Durg 9%
Bilaspur 18%

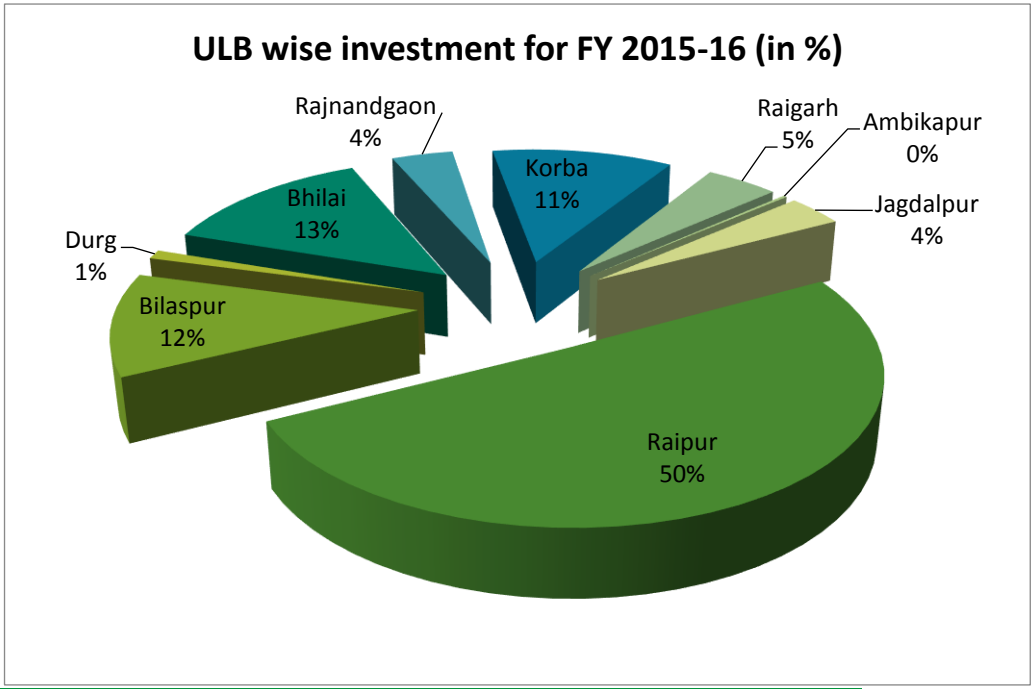
ULB wise investment for FY 2015-16 (in %)
Rajnandgaon 4%
Raigarh 5%
Ambikapur 0%
Korba 11%
Bhilai 13%
Jagdalpur 4%
Durg 1%
Bilaspur 12%
Raipur 50%

ULB wise investment in state for FY 2015-20 (in %)

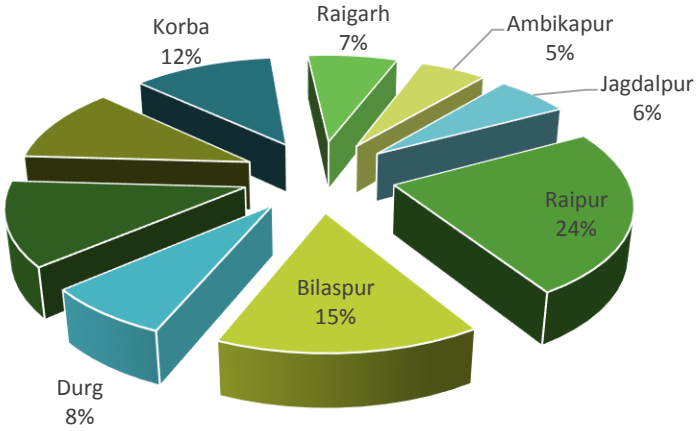

ULB wise distribution of Funds (2017-20)

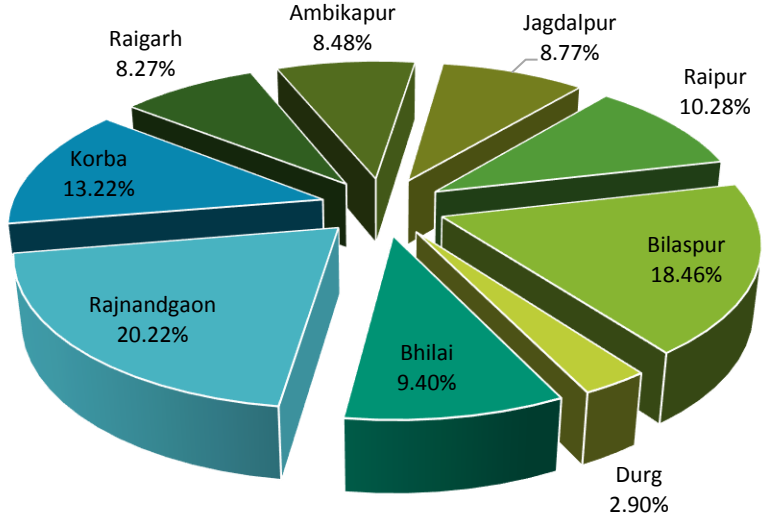

Table 3.4: SAAP - Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise) For the Financial Year 2016-2017

Sr. No	Name of ULB	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year 2015-16 & 2016-17							Proposed Spending during remaining Mission Period 2017 - 2020							Balance Carry Forward for Next Financial Years						
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total
1	Raipur	**524.40**	145.66	0.0	173.61	173.61	0.0	115.74	115.74	29.91	0.0	35.70	35.70	0.0	23.80	23.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Bilaspur	**332.15**	95.14	0.0	57.08	57.08	0.0	38.06	38.06	70.94	0.0	42.56	42.56	0.0	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Durg	**163.20**	29.57	0.0	17.74	17.74	0.0	11.83	11.83	52.04	0.0	31.22	31.22	0.0	20.81	20.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Bhilai	**266.73**	98.30	0.0	58.98	58.98	0.0	39.32	39.32	35.07	0.0	21.04	21.04	0.0	14.03	14.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Rajnandgaon	**241.68**	34.23	0.0	20.54	20.54	0.0	13.69	13.69	86.61	0.0	51.97	51.97	0.0	34.64	34.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Korba	**251.99**	85.39	0.0	51.23	51.23	0.0	34.15	34.15	40.61	0.0	24.37	24.37	0.0	16.24	16.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Raigarh	**161.20**	38.44	0.0	23.06	23.06	0.0	15.38	15.38	42.16	0.0	25.30	25.30	0.0	16.86	16.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Ambikapur	**118.98**	27.37	0.0	16.4	16.42	0.0	10.95	10.95	32.12	0.0	19.27	19.27	0.0	12.85	12.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Jagdalpur	**132.42**	30.96	0.0	18.58	18.58	0.0	12.38	12.38	35.25	0.0	21.15	21.15	0.0	14.10	14.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grand Total		**2192.75**	585.04	0.00	437.23	437.23	0.00	291.49	291.49	424.70	0.00	272.57	272.57	0.00	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHAPTER 2: REVIEW OF SAAPS

The state is required to prepare SAAP every year and get it approved by the Apex Committee. Before preparing the current year's SAAP, a key requirement is to review the performance of the approved SAAP of the previous years. This chapter reviews the performance of the implementation of the past SAAPs on key themes in the AMRUT Guidelines.

2.1 PROJECT COST AT A GLANCE:

Table 3.2: SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	186.75	330.65	7.00	524.40
2	Bilaspur	304.36	21.79	6.00	332.15
3	Durg	145.00	15.00	3.20	163.20
4	Bhilai	242.73	20.00	4.00	266.73
5	Rajnandgaon	223.68	14.00	4.00	241.68
6	Korba	229.99	18.00	4.00	251.99
7	Raigarh	148.00	10.00	3.20	161.20
8	Ambikapur	106.98	8.00	4.00	118.98
9	Jagdalpur	119.42	10.00	3.00	132.42
	TOTAL	1706.91	447.44	38.40	2192.75
Total Project Investments					2192.75
A&OE					80.78
Grand Total					2273.53

Table 3.2(a): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2016

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	10.00	2.40	61.40
2	Bilaspur	81.84	21.79	1.60	105.23
3	Durg	35.67	15.00	0.86	51.53
4	Bhilai	77.04	20.00	0.86	97.90
5	Rajnandgaon	26.94	12.00	0.86	39.80
6	Korba	67.12	18.00	0.86	85.98
7	Raigarh	32.15	10.00	0.86	43.01
8	Ambikapur	46.16	6.00	0.86	53.02
9	Jagdalpur	24.67	10.00	0.86	35.53
	TOTAL	440.59	122.79	10.02	573.40
Total Project Investments					573.40
A&OE					8.98
Grand Total					582.38

Table 3.2(b): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2016-2017

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	320.65	3.95	373.60
2	Bilaspur	81.85	0.00	3.20	85.05
3	Durg	5.88	0.00	1.72	7.60
4	Bhilai	96.97	0.00	1.72	98.69
5	Rajnandgaon	26.94	0.00	1.72	28.66
6	Korba	83.07	0.00	1.72	84.89
7	Raigarh	32.15	0.00	1.72	33.87
8	Ambikapur	0.00	0.00	1.72	1.72
9	Jagdalpur	24.67	0.00	1.72	26.39
TOTAL		400.53	320.65	19.19	740.37
Total Project Investments					740.37
A&OE					8.96
Grand Total					749.33

Table 3.2 (c): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2017-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	88.75	0.00	0.65	89.40
2	Bilaspur	140.68	0.00	1.20	141.88
3	Durg	103.45	0.00	0.62	104.07
4	Bhilai	68.72	0.00	1.42	70.14
5	Rajnandgaon	169.80	2.00	1.42	173.22
6	Korba	79.80	0.00	1.42	81.22
7	Raigarh	83.70	0.00	0.62	84.32
8	Ambikapur	60.82	2.00	1.42	64.24
9	Jagdalpur	70.08	0.00	0.42	70.50
	TOTAL	865.80	4.00	9.19	878.99
Total Project Investments					878.99
A&OE					62.84
Grand Total					941.83

2.2 PROJECT PROGRESS

The physical and financial progress of SAAP 2015 – 16 and 2016-17 is as follows:

Sr. No	Name ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
		Project name	Amount				Physical (%)	Financial (%)	
A. WATER SUPPLY									
1	**Bhilai**	Water Supply Scheme	174.01	Y	Y	Y	3	4.02	27.84
2	**Korba**	Water Supply Scheme	150.19	Y	Y	Y	5	16.65	24.03
3	**Bilaspur**	Water Supply Scheme	163.69	Y	Y	N	NA	NA	26.19
4	**Rajnandgaon**	Water Supply Scheme	53.88	Y	Y	N	NA	NA	8.62
5	**Raipur**	Water Supply Scheme	98.00	Y	Y	N	NA	NA	14.37
6	**Jagdalpur**	Water Supply Scheme	49.34	Y	Y	N	NA	NA	7.89
7	**Ambikapur**	Water Supply Scheme	46.16	Y	Y	N	NA	NA	7.39
8	**Durg**	Water Supply Scheme	41.55	N	N	N	NA	NA	6.65
9	**Raigarh**	Water Supply Scheme	64.30	N	N	N	NA	NA	10.29
Subtotal (A)			841.12						133.27
B. SEWERAGE & SEPTAGE MANAGEMENT									
10	**Rajnandgaon**	Septage Management	11.78	Y	Y	N	NA	NA	1.92
11		Procurement of Septage Management Equipment	0.77	Y	Y	Y	40	40	
12	**Korba**	Septage Management	17.00	N	N	N	NA	NA	2.88
13		Procurement of Septage Management Equipment	1.00	Y	Y	Y	55	50	
14	**Bilaspur**	Septage Management	20.44	N	N	N	NA	NA	3.49
15		Procurement of Septage Management Equipment	1.35	Y	Y	Y	45	41	
16	**Durg**	Septage Management	14.8	N	N	N	NA	NA	2.40

Sr. No	Name ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
		Project name	Amount				Physical (%)	Financial (%)	
17		Procurement of Septage Management Equipment	0.20	Y	Y	Y	39	30	
18	Raipur	Sewerage	320.65	N	N	N	NA	NA	48.49
19		Septage Management	7.99	N	N	N	NA	NA	
20		Procurement of Septage Management Equipment	2.01	Y	Y	Y	31	25	
21	Raigarh	Septage Management	9.34	N	N	N	NA	NA	1.60
22		Procurement of Septage Management Equipment	0.66	Y	Y	Y	36	30	
23	Ambikapur	Septage Management	5.80	N	N	N	NA	NA	0.96
24		Procurement of Septage Management Equipment	0.20	Y	Y	Y	60	52	
25	Bhilai	Septage Management	18.44	N	N	N	NA	NA	3.20
26		Procurement of Septage Management Equipment	1.56	Y	Y	Y	45	40	
27	Jagdalpur	Septage Management	9.34	N	N	N	NA	NA	1.60
28		Procurement of Septage Management Equipment	0.66	Y	Y	Y	41	35	
Subtotal (B)			443.99						66.54
C. Parks and Green Spaces									
28	Raipur	Development of Garden at Ward No 2	1.15	Y	Y	Y	7	NA	0.98
29		Development of Garden FY 15-16	1.25	N	N	N	NA	NA	
		Development of Garden at Ward	0.57	Y	Y	Y	4	NA	

Sr. No	Name ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
		Project name	Amount				Physical (%)	Financial (%)	
30		No 24							
31		Development of Garden FY 16-17	3.38	N	N	N	NA	NA	
32	Bilaspur	Development of Garden at 5 Wards	0.84	Y	Y	Y	7	NA	0.77
33		Development of Garden FY 15-16	0.76	N	N	N	NA	NA	
34		Development of Garden at Ward No 11	0.37	Y	Y	Y	10	NA	
35		Development of Garden FY 16-17	2.83	N	N	N	NA	NA	
36	Durg	Development of Garden at Katul Board	0.30	Y	Y	Y	6	NA	0.41
37		Development of Garden FY 15-16	0.56	N	N	N	NA	NA	
38		Development of Garden at Ward No 45	0.83	Y	Y	Y	2	NA	
39		Development of Garden FY 16-17	0.89	N	N	N	NA	NA	
40	Bhilai	Development of Garden at Ward No 7	0.50	Y	Y	Y	10	NA	0.41
41		Development of Garden FY 15-16	0.36	N	N	N	NA	NA	
42		Development of	0.44	Y	Y	Y	12	NA	

Sr. No	Name ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
		Project name	Amount				Physical (%)	Financial (%)	
		Garden at Ward No 3							
43		Development of Garden FY 16-17	1.28	N	N	N	NA	NA	
44	Rajnandgaon	Development of Garden at Ward No 7	0.33	Y	Y	Y	6	NA	0.41
45		Development of Garden FY 15-16	0.53	N	N	N	NA	NA	
46		Development of Garden at Ward No 31	0.59	Y	Y	Y	4	NA	
47		Development of Garden FY 16-17	1.13	N	N	N	NA	NA	
48	Korba	Development of Garden at Ward No 24	0.42	Y	Y	Y	14	NA	0.41
49		Development of Garden FY 15-16	0.44	N	N	N	NA	NA	
50		Development of Garden at Ward No 51	0.75	Y	Y	Y	12	NA	
		Development of Garden FY 16-17	0.97	N	N	N	NA	NA	
51	Raigarh	Development of Garden at Ward No 27	0.39	Y	Y	Y	6	NA	0.41
52		Development of Garden FY 15-16	0.47	N	N	N	NA	NA	
53		Development of	0.43	Y	Y	Y	3	NA	

Sr. No	Name ULB	Approved SAAP		DPR (Y/N)	SLTC (Y/N)	Work Order (Y/N)	Implementation Progress		Amount disbursed till date
		Project name	Amount				Physical (%)	Financial (%)	
		Garden at Ward No 39							
54		Development of Garden FY 16-17	1.29	N	N	N	NA	NA	
55	Ambikapur	Development of Garden at Ward No 19	0.28	Y	Y	Y	15	NA	0.41
56		Development of Garden FY 15-16	0.58	N	N	N	NA	NA	
57		Development of Garden at Ward No 7	0.27	Y	Y	Y	9	NA	
58		Development of Garden FY 16-17	1.45	N	N	N	NA	NA	
59	Jagdalpur	Development of Garden at Ward No 32	0.55	Y	Y	Y	5	NA	0.41
		Development of Garden FY 15-16	0.31	N	N	N	NA	NA	
60		Development of Garden at Ward No 8	0.32	Y	Y	Y	3	NA	
61		Development of Garden FY 16-17	1.40	N	N	N	NA	NA	
Subtotal (C)			29.21						4.62

- **Have DPRs been prepared for all projects approved earlier? If not, then which are the projects for which DPR is pending and why?**

  Detailed Project Reports for seven water supply projects for the cities of Bhilai, Korba, Raipur, Bilaspur, Ambikapur, Jagdalpur and Rajnandgaon have been prepared. Also septage management project of Rajnandgaon has been prepared. Further, DPRs for water supply scheme of 2 cities (Raigarh and Durg) and sewerage/septage schemes for 8 cities (except Rajnandgaon) are currently being prepared and will be completed by 31st March 2017.

  DPR preparation was delayed due to non-availability of reliable field data, as none of the mission cities had previously undertaken detailed engineering survey to collect information/ data regarding infrastructure status. Therefore, in order to get current and reliable data for preparation of DPRs of respective mission cities, detailed engineering survey was carried out in each city. DPR preparation was preceded by detailed engineering survey and data collection work.

- **What is the plan of action for the pending DPRs?**

  Detailed engineering surveys have been completed in all the mission cities and data shared for preparation of DPRs of respective cities under different sectors. Currently, DPRs are being prepared and will be completed by 31st March, 2017.

- **How many SLTC meetings had been held in the State? How many DPRs have been approved by the SLTC till date?**

  6 SLTC meetings have been held so far. SLTC meeting were held on 8th January, 21nd March 19th May 2016, 16th September 2016, 04th November 2016 and 4th February 2017.

  DPR's as mentioned below have been approved:

Sr. No	Name of the ULB	Project Name	Project Cost (in Cr.)
1	Raipur	Water Supply Scheme	186.75
		Procurement of Septage Management Equipment	2.01
		Development of Garden at Ward No 2	1.15
		Development of Garden at Ward No 24	0.57
2	Bilaspur	Water Supply Scheme	212.72
		Procurement of Septage Management Equipment	1.35
		Development of Garden at 5 Wards	0.84
		Development of Garden at Ward No 11	0.37

3	Durg	Procurement of Septage Management Equipment	0.20
		Development of Garden at Ward No 45	0.83
		Development of Garden at Katul Board	0.30
4	Bhilai	Water Supply Scheme	240.73
		Procurement of Septage Management Equipment	1.56
		Development of Garden at Ward No 7	0.50
		Development of Garden at Ward No 3	0.44
5	Rajnandgaon	Water Supply Scheme	223.68
		Septage Management Scheme	11.78
		Procurement of Septage Management Equipment	0.77
		Development of Garden at Ward No 7	0.33
		Development of Garden at Ward No 31	0.59
6	Korba	Water Supply Scheme	229.99
		Procurement of Septage Management Equipment	1.00
		Development of Garden at Ward No 24	0.42
		Development of Garden at Ward No 51	0.75
7	Raigarh	Procurement of Septage Management Equipment	0.66
		Development of Garden at Ward No 27	0.39
		Development of Garden at Ward No 39	0.43

8	Ambikapur	Water Supply Scheme	106.98
		Procurement of Septage Management Equipment	0.20
		Development of Garden at Ward No 19	0.28
		Development of Garden at Ward No 7	0.27
9	Jagdalpur	Water Supply Scheme	119.42
		Procurement of Septage Management Equipment	0.66
		Development of Garden at Ward No 32	0.55
		Development of Garden at Ward No 8	0.32

- By when will the pending DPRs be approved by the SLTC and when will implementation start?

  All the DPRs will be approved by April 2017 and implementation of the projects will start from June 2017. It is being envisaged that execution of all the projects will be completed by March 2020.

- Based on the identification of delayed projects and the reasons for slow physical progress, what is the plan of action to speed-up the projects?

  Implementation of all the approved projects is on time and physical progress is as per schedule. In order to monitor the progress of project implementation, either the PDMC will be strengthened or individual consultants will be appointed for such delayed projects, if any.

- How much amount has been utilized and what is the percentage share of the funding agencies? Are there any deviations from the approved funding pattern approved by the Apex Committee?

  An amount of RS. 16.73 Cr has been utilized as on 28 February, 2017. The sharing pattern is given below as per the AMRUT guidelines: -

Type of City	Sharing Pattern		
	Centre	State	ULB
Above million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	33.33%	40%	26.67%
Below million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	50%	30%	20%
Others (Green spaces & parks)	50%	30%	20%

- **List out the projects where release of funds to ULBs by the State was delayed?**

  There is no such instance.

- **In how many ULBs implementation was done by agencies other than ULBs? Was a resolution taken from all ULBs?**

  In Korba, Rajnandgaon, Ambikapur and Bilaspur implementation of few components of water supply projects has to be been done by agencies other than ULB.

  Yes – Resolution has been taken from all the ULBs also tripartite MoU will be signed as per mission guidelines.

- **List out the projects where the assessed value approved by the Apex Committee was greater than the tendered value and there was a saving? Was this addressed by the HPSC in the present SAAP?**

  There is no such instance yet where the assessed value approved by the Apex Committee was greater than the tendered value and there was a saving.

- **List out the number of city-wise projects where the second and third installments were claimed.**

  NA

- **List out the city-wise completed projects. Was the targeted benchmark achieved? Explain the reasons for non-achievement.**

  No project has been completed.

- **List out the details of projects taken up in PPP model. Describe the type of PPP.**

  Till date no project has been taken up on PPP mode.

- **List out and describe any out-of-the-box initiatives/Smart Solutions/resilience used/incorporated in the projects under implementation.**

  - **Application of PLC and SCADA:** Extensive application of PLC and SCADA has been adopted in the projects for better operation and maintenance practices and for optimum use of available resources.
  - **Application of Hydraulically Operated Diaphragm Valves:** Application of Hydraulically operated diaphragm type valves to control flow and pressure along with OHSR management. Use of such valves will substantially decrease the O&M charges and required number of Manpower is also very less.
  - **GIS Mapping:** GIS mapping of all the assets of water supply scheme, which will help in reducing NRW and improve record keeping for O & M and future planning.

2.3 SERVICE LEVELS

Name of City	Service Level Benchmark	SAAP Baseline (as in 2015)	SAAP Mission Target	For the last Financial Year	
				Target up to beginning of current FY	Achievement up to beginning of current FY*
Water Supply	1.Household level coverage of direct water	45.12	100	-	-
	2. Per capita quantum of	98.16	135	-	-
	3. Quality of water	81.14	100	-	-
Sewerage & Septage Management	4. Coverage of latrines (individual or community)	69.92	100	-	-
	5. Coverage of sewerage network services	4.67	100	-	-
	6. Efficiency of Collection of Sewerage	6.67	100	-	-
	7. Efficiency in treatment	8.33	100	-	-

** No project has been completed yet.*

- **In how many projects, city-wise, have targets not been achieved? What is the Plan of Action to achieve the targets?**

  NA

- **What are the status of the ongoing DPR preparation and the plan of action for the pending DPRs?**

  Detailed Project Reports for seven water supply projects for the cities of Bhilai, Korba, Raipur, Bilaspur, Ambikapur, Jagdalpur and Rajnandgaon have been prepared. Also septage management project of Rajnandgaon has been prepared. Further, DPRs for water supply scheme of 2 cities (Raigarh and Durg) and sewerage/septage schemes for 8 cities (except Rajnandgaon) are currently being prepared and will be completed by 31st March 2017.

  DPR preparation was delayed due to non-availability of reliable field data, as none of the mission cities had previously undertaken detailed engineering survey to collect information/ data regarding infrastructure status. Therefore, in order to get current and reliable data for preparation of DPRs of respective mission cities, detailed engineering survey was carried out in each city. DPR preparation was preceded by detailed engineering survey and data collection work.

- **How many SHPSC meetings had been held in the State? How many DPRs have been approved by the SHPSC till date?**

  3 SHPSC meeting has been held on 20th October, 2015 and 20th May, 2016 and 23rd February, 2017. All the projects that are approved by SLTC has been approved by the SHPSC.

2.4 CAPACITY BUILDING

MoU for Capacity Building under all the 4 components has been signed with Engineering Staff College of India (ESCI), Hyderabad and All India Institute of Local Self Government(AIILSG), New Delhi.

Sr. No	Name of ULB	Name of Department	Total no. to be trained in Mission period	Target to be trained during the previous FY	No. fully trained during previous FY	Name training institute
1	**Raipur**	Elected Representative	16	16	16	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	23	12	12	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	18	9	9	AIILSG, New Delhi
		Town Planning Department	12	12	12	NA
		Administrative Department	5	5	5	AIILSG, New Delhi
2	**Bilaspur**	Elected Representative	15	15	15	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	12	6	6	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	16	8	8	AIILSG, New Delhi
		Town Planning Department	4	0	0	NA
		Administrative Department	10	10	10	AIILSG, New Delhi
3	**Durg**	Elected Representative	14	14	14	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	12	6	6	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	10	5	5	AIILSG, New Delhi
		Town Planning Department	8	0	0	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	5	5	5	AIILSG, New Delhi
4	**Bhilai**	Elected Representative	16	16	16	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	10	5	5	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	16	8	8	AIILSG, New Delhi
		Town Planning Department	5	0	0	NA

Sr. No	Name of ULB	Name of Department	Total no. to be trained in Mission period	Target to be trained during the previous FY	No. fully trained during previous FY	Name training institute
		Administrative Department	8	8	8	AIILSG, New Delhi
5	**Rajnandgaon**	Elected Representative	12	12	12	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	6	6	6	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	10	5	5	ESCI, Hyderabad
		Town Planning Department	5	5	5	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	6	6	6	AIILSG, New Delhi
6	**Korba**	Elected Representative	15	0	0	AIILSG, New Delhi
		Finance Department	19	19	19	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	24	12	12	ESCI, Hyderabad
		Town Planning Department	7	7	7	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	20	20	20	AIILSG, New Delhi
7	**Raigarh**	Elected Representative	11	11	11	ESCI, Hyderabad
		Finance Department	11	11	11	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	8	4	4	ESCI, Hyderabad
		Town Planning Department	6	6	6	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	7	7	7	AIILSG, New Delhi
8	**Ambikapur**	Elected Representative	7	7	7	ESCI, Hyderabad
		Finance Department	11	11	11	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	10	5	5	ESCI, Hyderabad
		Town Planning Department	4	4	4	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	12	12	12	AIILSG, New Delhi

Sr. No	Name of ULB	Name of Department	Total no. to be trained in Mission period	Target to be trained during the previous FY	No. fully trained during previous FY	Name training institute
9	**Jagdalpur**	Elected Representative	5	5	5	ESCI, Hyderabad
		Finance Department	8	8	8	AIILSG, New Delhi
		Engineering Department	8	4	4	ESCI, Hyderabad
		Town Planning Department	6	6	6	ESCI, Hyderabad
		Administrative Department	12	12	12	AIILSG, New Delhi
	TOTAL		**485**	**365**	**365**	

- **In how many departments was training completed as approved in the SAAP of the last Financial Year? In how many departments was training partially done and in how many departments training not done at all? Please give reasons**

  Targets have been met out in all the departments.

- **List out the training institutes that could not complete training of targeted functionaries. What were the reasons and how will this be avoided in future?**

  NA

- **What is the status of utilization of funds?**

  Funds for Capacity Building is met by CBUD Funds and claims are being sent to MoUD regularly on receipt from the concerned institute.

- **Have the participants visited best practice sites?**

  Exposure visits of officials and elected representatives to the best practices sites will be conducted in the current financial year.

- **Have the participants attended any national/international workshops, as per guideline (Annexure 7)?**

  No, so far participants have not attended any National or international workshops. However, a state level workshop is being planned.

- **What is the plan of action for the pending activities, if any?**

  Till date targets have been achieved.

2.5 REFORMS

- **Have the Reform formats prescribed by the TCPO furnished?**

  Yes

- **Did the State as a whole complete 70 percent of Reforms? If, yes was the incentive claimed?**

  As per the current status state will achieve the reform target of FY 2016-17, the incentive of Rs 33.60Cr. will be claimed before 30th April, 2017.

- **What was the amount of incentive claimed? How was it distributed among the ULBs and what was it used for?**

- **The amount of incentive claimed for FY 2015-17 was Rs. 29.025 Crore, however the state received incentive of Rs. 13 Crore only. SHPSC has decided to utilize the amount of reform incentive for implementation of reforms.**

- **What is the status of Reforms to be completed in the Mission period? Has advance action been taken and a Plan of Action prepared?**

  In total of 11 set of reforms having 52 milestones will be achieved as per the timeline stipulated in the AMRUT guidelines. The Plan of Action for the same is prepared and actions are taken accordingly.

- **Give any instances of innovation in Reform implementation.**

  NA

2.6 USE OF A&OE

- **What are the items for which the A&OE has been used?**

  The amount of A&OE allocated to the state for FY 2015-16 was Rs 8.98 crore and for 2016-17 Rs 8.96 crore out of which state has received only 2.25 crore. The UC and proposal for release of next instalment has already been submitted. The received amount has been utilized under the following components/Items: -

Sl No	Items for A&OE
1	Remuneration for PDMC
2	Remuneration for SMMU
3	Remuneration for CMMU
4	Survey Work for DPR Preparation
5	Other administrative expenses.

- **Are the items similar to the approved items in SAAP or there is any deviation? If yes, list the items with reasons**

  Yes, the items similar to the approved SAAP and there is no deviation.

- **What is the utilization status of funds?**

  Out of the total allocated amount of Rs 80.78 crore to the state for the entire mission period, Rs 2.25 crore has been received and completely utilized.

- **Has the IRMA been appointed? What was the procedure followed?**

  As per the instructions issued by GoI, the appointment of agency for IRMA will be done by MoUD itself

- **If not appointed, give reason for delay and the likely date of appointment.**

  IRMA agency will be appointed by Government of India.

- **Have you taken up activities connected to E-Municipality as a Service (E-MAAS)? Please give details.**

  Yes the activities have been undertaken. The details are annexed with reform incentive claim form.

- **Have you displayed the logo and tagline of AMRUT prominently on all projects? Please give list.**

  Yes.

- **Have you utilized the funds on any of the inadmissible components (para 4.4)? If yes, give list and reasons.**

  No

2.7 FUNDS FLOW

Sr. No	Name of the ULB	Project Name	Project Cost (in Cr.)
1	Raipur	Water Supply Scheme	186.75
		Procurement of Septage Management Equipment	2.01
		Development of Garden at Ward No 2	1.15
		Development of Garden at Ward No 24	0.57
2	Bilaspur	Water Supply Scheme	212.72
		Procurement of Septage Management Equipment	1.35
		Development of Garden at 5 Wards	0.84
		Development of Garden at Ward No 11	0.37
3	Durg	Procurement of Septage Management Equipment	0.20
		Development of Garden at Ward	0.83

		No 45	
		Development of Garden at Katul Board	0.30
4	Bhilai	Water Supply Scheme	240.73
		Procurement of Septage Management Equipment	1.56
		Development of Garden at Ward No 7	0.50
		Development of Garden at Ward No 3	0.44
5	Rajnandgaon	Water Supply Scheme	223.68
		Septage Management Scheme	11.78
		Procurement of Septage Management Equipment	0.77
		Development of Garden at Ward No 7	0.33
		Development of Garden at Ward No 31	0.59
6	Korba	Water Supply Scheme	229.99
		Procurement of Septage Management Equipment	1.00
		Development of Garden at Ward No 24	0.42
		Development of Garden at Ward No 51	0.75
7	Raigarh	Procurement of Septage Management Equipment	0.66
		Development of Garden at Ward No 27	0.39
		Development of Garden at Ward No 39	0.43
8	Ambikapur	Water Supply Scheme	106.98
		Procurement of Septage	0.20

		Management Equipment	
		Development of Garden at Ward No 19	0.28
		Development of Garden at Ward No 7	0.27
9	Jagdalpur	Water Supply Scheme	119.42
		Procurement of Septage Management Equipment	0.66
		Development of Garden at Ward No 32	0.55
		Development of Garden at Ward No 8	0.32

- **In how many projects, city-wise, has the full funds been sanctioned and disbursed?**

  No, project under AMRUT has completed yet. Therefore, full funds have not been disbursed to ULBs.

- **Identify projects where delay in funds release led to delay in project implementation?**

  NA. There is no such instance.

- **Give instances of doing more with less during implementation.**

  NA. There is no such instance.

2.8 FUND DISBURSEMENTS AND CONDITIONS

- **How many project fund request has been made to the GoI?**

  The state has received its 1st installment of Rs. 55.29 Cr. of SAAP-I and Rs. XX Cr. of SAAP-II. No request for 2nd and 3rd installment has been made yet.

- **How many installments the GoI has released?**

  Only 1st installment has been released.

- **Is there any observation from the GoI regarding the claims made?**

  No.

- **List out the conditions imposed by the Apex Committee, State HPSC and the SLTC. Have all the conditions been complied with? If, no identify the conditions not complied with and give reasons for non-compliance.**

  Yes, all the conditions have been complied with.

  The following conditions have been imposed by the APEX committee in the meeting held on 26th November, 2015.

i. **State government need to clearly indicate about the availability of Land and other clearances. No project should be approved by State Level Technical Committee (SLTC) which do not have land available and no work order should be issued till receipt of all clearances from all concerned departments/authorities.**

ii. **Action Plan for recycling/reuse of waste water and reduction of NRW should be placed before the SLTC at the time of appraisal of DPRs.**

iii. **The state government should try to attain convergence between the AMRUT & SBM according to Mission Guidelines.**

iv. **The break-up of coverage with sewerage network (centralized and decentralized) and septage (septic tanks) may be clearly brought out during DPR approval by SLTC.**

v. **Estimates in the SAAP should be based on SSR and not on market rates.**

vi. **Water Quality should also be analyzed at the consumer end.**

vii. **Capacity Building details to be provided to NIUA/MoUD. A useful starting point will be to train all engineers who have made the SLIPs/ SAAP.**

viii. **Implementation of reforms will make State/UTs eligible for annual incentive. In order to get incentives reforms should be broken up into activities with timeline and sent to TCPO by the State Mission Director.**

CHAPTER 3: STATE ANNUAL ACTION PLAN (SAAP)

Table 3.1: SAAP – Master Plan of all projects details to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Name of ULB (water supply and sewerage)	Total number of projects to achieve universal coverage *			Estimated Cost (In Cr.)			Number of years to achieve universal coverage
		Water Supply	Sewerage/ Septage	Total	Water Supply	Sewerage/ Septage	Total	
1	Raipur	5	3	8	186.75	330.65	517.40	5
2	Bilaspur	2	2	4	304.36	21.79	326.15	5
3	Durg	1	1	2	145.00	15.00	160.00	5
4	Bhilai	7	1	8	242.73	20.00	262.73	5
5	Rajnandgaon	1	2	3	223.68	14.00	237.68	5
6	Korba	8	1	9	229.99	18.00	247.99	5
7	Raigarh	1	1	2	148.00	10.00	158.00	5
8	Ambikapur	1	2	3	106.98	8.00	114.98	5
9	Jagdalpur	1	1	2	119.42	10.00	129.42	5
Grand Total		27	14	41	1706.91	447.44	2154.35	5
Note - No of projects may vary as per implementation schedule								

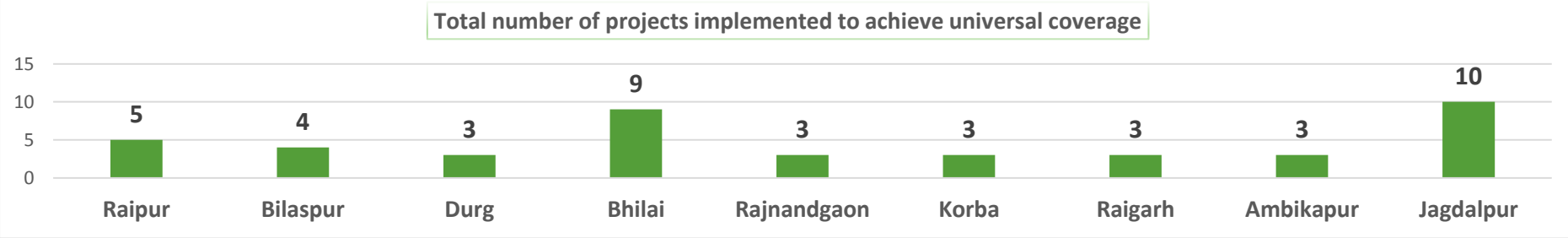

Table 3.5: SAAP – State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
Water Supply	**1706.91**	1. Household level coverage of direct water supply connections	**45.12**	-	-	-	-	**78.00**	**100.0**
		2. Per capita quantum of water supplied	**98.16**	-	-	-	-	**120.00**	**135.00**
		3. Quality of water supplied	**81.14**	-	-	-	-	**97.40**	**100.00**
Sewerage and Septage Management	**447.44**	4. Coverage of latrines (individual or community)	**69.92**	-	-	**95.20**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
		5. Coverage of sewerage network services	**4.67**	-	-	**6.69**	**33.50**	**78.80**	**100.00**
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	**6.67**	-	-	**7.30**	**40.30**	**85.70**	**100.00**
		7. Efficiency in treatment	**8.33**	-	-	-	**26.89**	**87.34**	**100.00**
Others (Green Spaces & Parks)	**38.40**	**No SLB study of parks and green spaces has been conducted yet. However at least one park in each mission city will be developed every year.**							

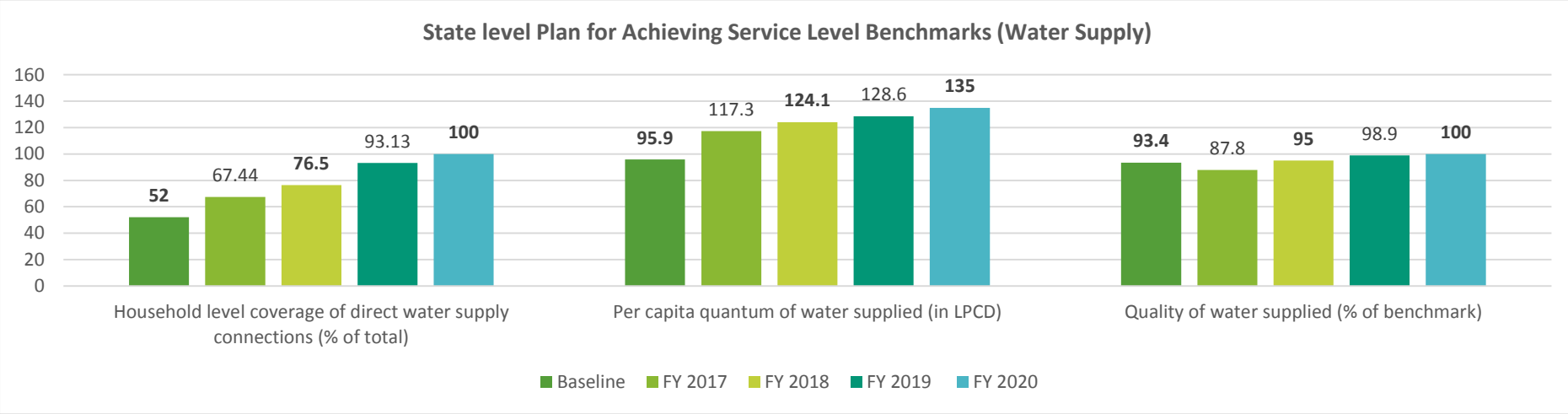
State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks (Water Supply)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
52
67.44
76.5
93.13
100
95.9
117.3
124.1
128.6
135
93.4
87.8
95
98.9
100
Household level coverage of direct water supply connections (% of total)
Per capita quantum of water supplied (in LPCD)
Quality of water supplied (% of benchmark)
Baseline
FY 2017
FY 2018
FY 2019
FY 2020

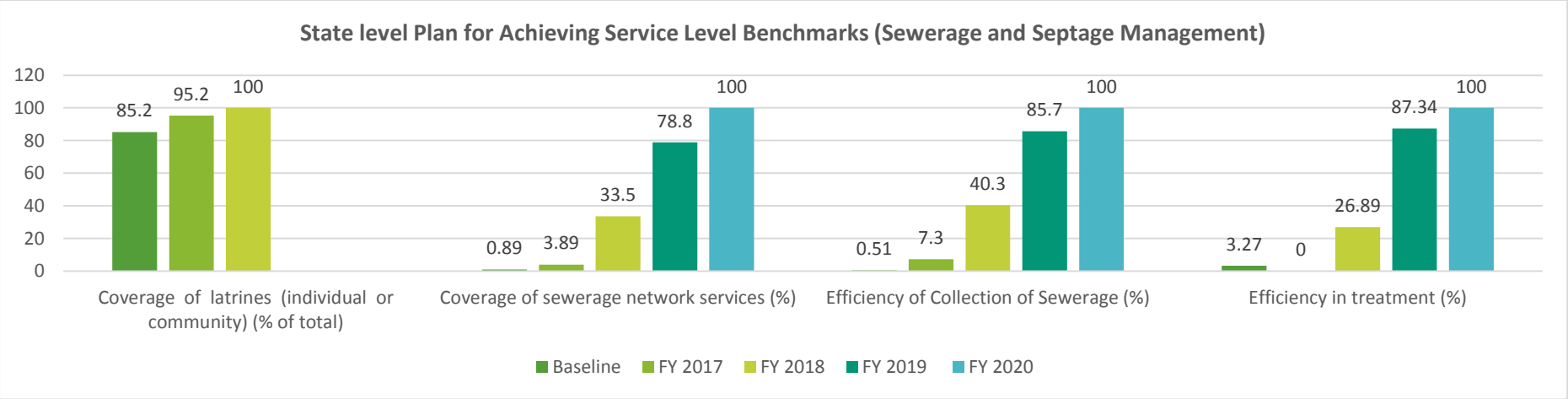
State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks (Sewerage and Septage Management)
120
100
80
60
40
20
0
85.2
95.2
100
0.89
3.89
33.5
78.8
100
0.51
7.3
40.3
85.7
100
3.27
0
26.89
87.34
100
Coverage of latrines (individual or community) (% of total)
Coverage of sewerage network services (%)
Efficiency of Collection of Sewerage (%)
Efficiency in treatment (%)
Baseline
FY 2017
FY 2018
FY 2019
FY 2020

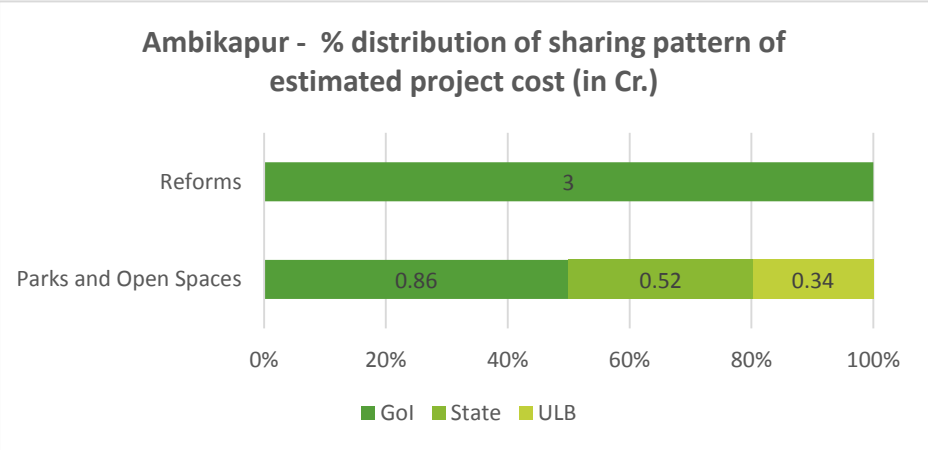
Ambikapur - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
3
0.86
0.52
0.34
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

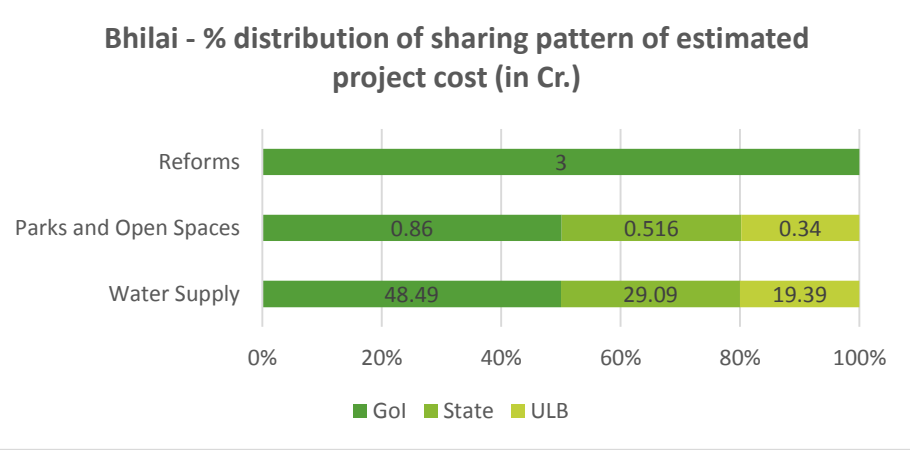
Bhilai - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.34
48.49
29.09
19.39
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

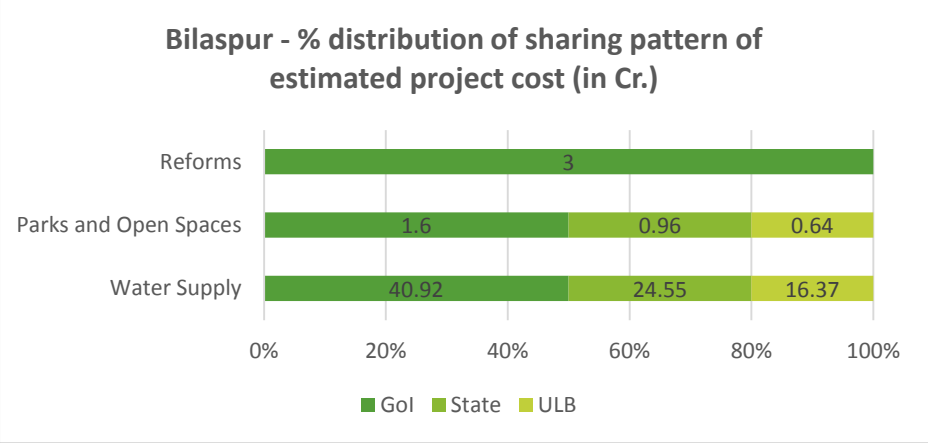
Bilaspur - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
1.6
0.96
0.64
40.92
24.55
16.37
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

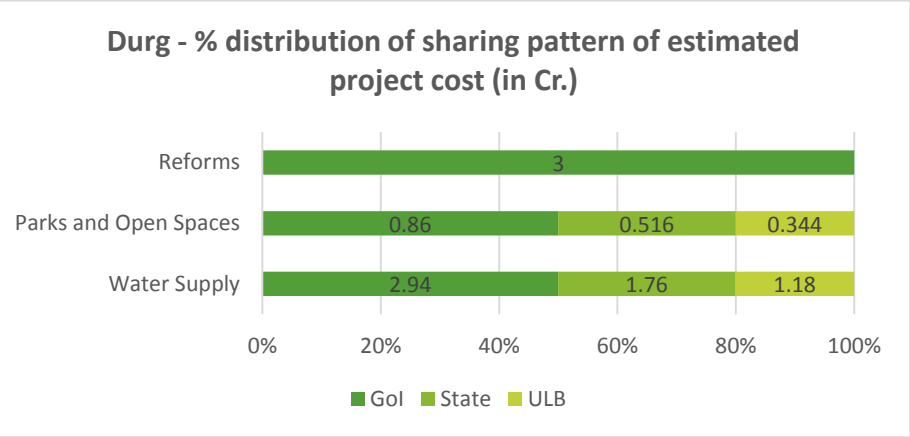
Durg - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.344
2.94
1.76
1.18
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

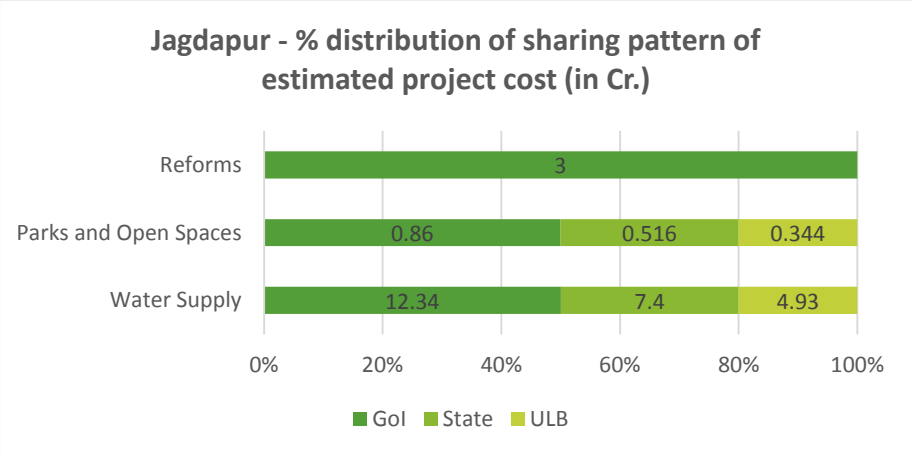
Jagdapur - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.344
12.34
7.4
4.93
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

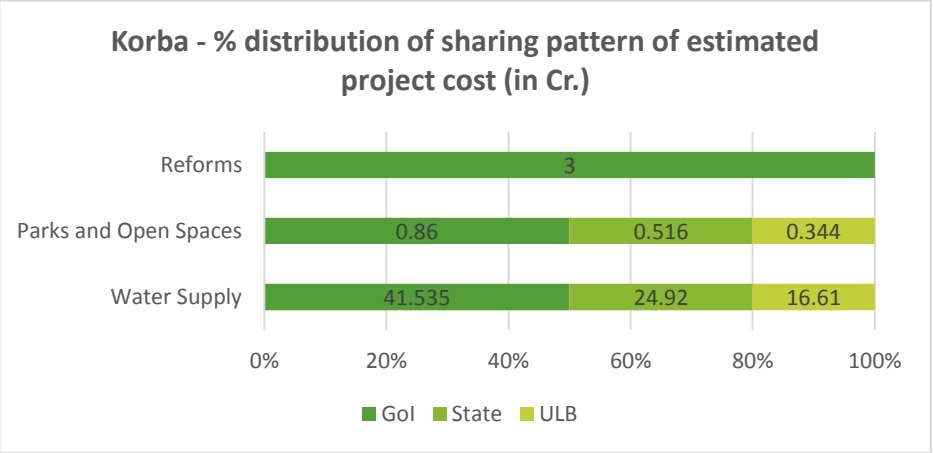
Korba - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.344
41.535
24.92
16.61
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

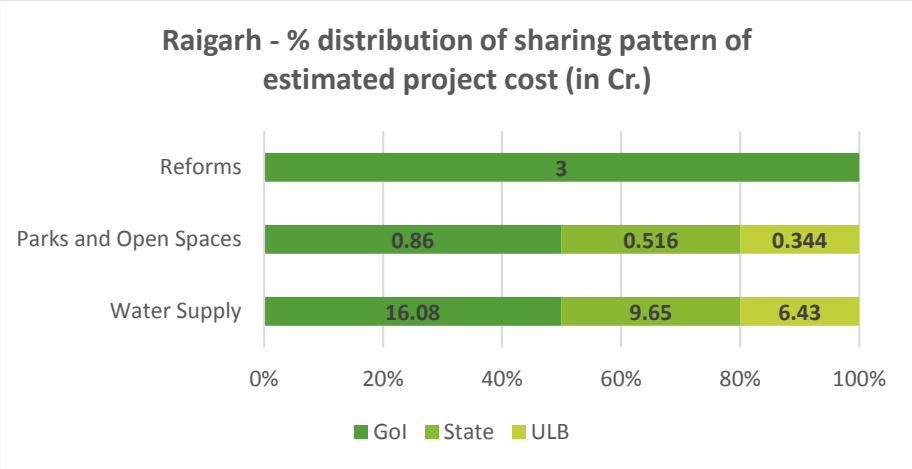
Raigarh - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.344
16.08
9.65
6.43
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

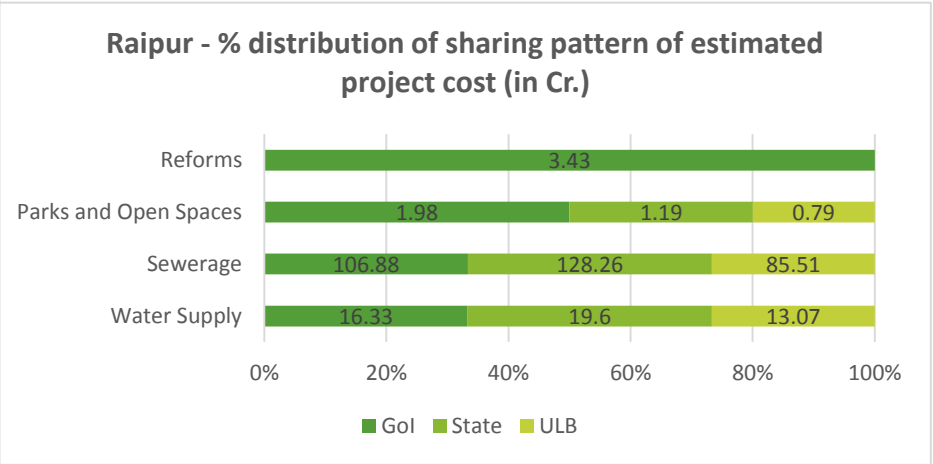
Raipur - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Sewerage
Water Supply
3.43
1.98
1.19
0.79
106.88
128.26
85.51
16.33
19.6
13.07
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GoI
State
ULB

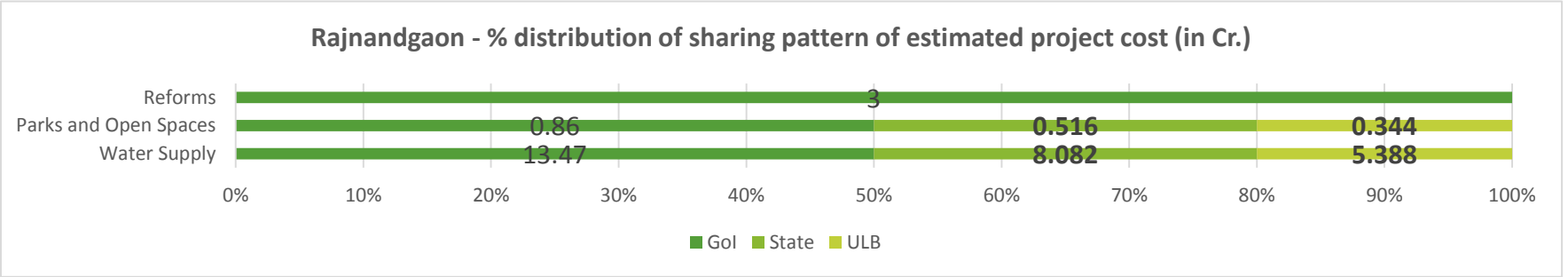
Rajnandgaon - % distribution of sharing pattern of estimated project cost (in Cr.)
Reforms
Parks and Open Spaces
Water Supply
3
0.86
0.516
0.344
13.47
8.082
5.388
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GoI
State
ULB

3.1 PRINCIPLES OF PRIORITIZATION

- **Has consultation with local MPs/ MLAs, Mayors and Commissioners of the concerned ULBs been carried out prior to allocation of funding? Give details of dates and number of participants.**

  Yes, all the stakeholders i.e. Commissioners/ Chief Municipal Officers, Elected Representatives, technical officers as well as citizens of the concerned cities have been consulted prior to allocation of funds. Details of citizen and stakeholder consultation are given in the SAAP

- **Has financially weaker ULBs given priority for financing?**

  Yes, proposals (as provided in SLIP) of all the 9 cities for achieving universal coverage have been considered in SAAP. Equal opportunity has been given to all the ULBs based on service level gap for achieving universal coverage.

- **Is the ULB with a high proportion of urban poor has received higher share? Please give list.**

  Yes, the sharing pattern is given below as per the AMRUT guidelines.

Type of City	Sharing Pattern		
	Centre	State	ULB
Above million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	33.33%	40%	26.67%
Below million plus cities (water supply & sewerage, septage management)	50%	30%	20%
Others (Green spaces & parks)	50%	30%	20%

- **Has the potential Smart cities been given preference? Please give list**

  Yes, in the state of Chhattisgarh two cities – Raipur and Bilaspur have been selected to be developed as Smart Cities. Therefore, preference has been given to these cities while allocating funds. In total mission outlay share of Raipur and Bilaspur is as under:

Year	Raipur	Bilaspur
FY 2015 – 16	11.03%	18.5%
FY 2016 - 17	49.11%	12%

- **What is the quantum of Central Assistance (CA) allocated to the State during 2017-20?**

  The quantum of Central Assistance allocated to the state for the year 2017 – 20 is Rs. 424.70 Cr. Sector wise breakup of the central share of Rs. 424.70 is as follows:

  a. **Water Supply – Rs. 418.11 Cr.**
  b. **Sewerage – Rs. 2.00 CR**
  c. **Parks – Rs. 9.19 cr**

ULB wise breakup of the allocation of Central Assistance is as follows:

Sr. No	Name of the ULB	Central Assistance (in Rs. Cr.)
1	**Raipur**	29.91
2	**Bilaspur**	70.94
3	**Durg**	52.04
4	**Bhilai**	35.07
5	**Rajnandgaon**	86.81
6	**Korba**	40.61
7	**Raigarh**	42.16
8	**Ambikapur**	32.12
9	**Jagdalpur**	35.25
	Total	**424.70**

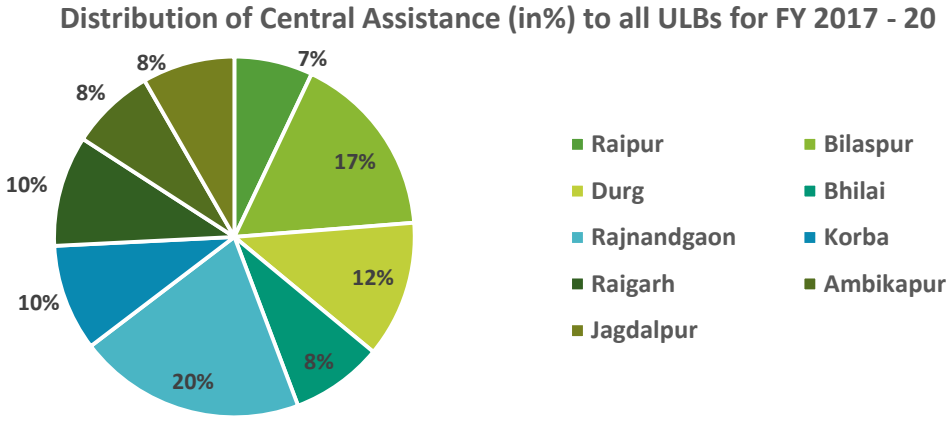

As per DO No. K-14012/95/2015 AMRUT-I, Dated 6th June, 2016, total ACA (Additional central allocation) for the state of Chhattisgarh is Rs. 1009.74 crores. Out of the total allocation of 1009.74 crores, Rs.276.47 was allocated for FY 2015 – 16, Rs.336.00 allocated for FY 2016-17 and Rs.397. 27 allocated for the remaining mission period (2017 – 20).

Total Central allocation in SAAP prepared and submitted for FY 2015-16 was Rs.290.25 crores. However, an approval was given for only 276.47 crores.

Central allocation in SAAP prepared and submitted for FY 2016-17 was Rs. 336.00 crores, but approved amount was only 308.57 crores. This implies that out of the total amount of 1009.74 crores ACA of only Rs. 585.04 crores (Rs.276.47+Rs.308.57) has been approved and sanctioned to the state government.

Now the balance amount of Rs. 424.70 (Total ACA Rs.1009.74 – Rs 585.04) is being adjusted in the current SAAP with central allocation being taken as Rs. 424.70 for the remaining mission period (2017 – 2020)

- **Has the allocation to different ULBs within State is consistent with the urban profile of the state?**

  Yes, the urban profile of respective ULBs have been considered while disbursement of FFC grant as ULB share.

3.2 IMPORTANCE OF O&M

Table 4: Broad proposed allocations for administrative and other expenses

Sr. No	Items proposed for A&OE	Total Allocation	Committed Expenditure from previous year (if any)	Proposed spending for Current Financial year (2017-18)	Balance to Carry Forward	
					FY 2018-19	FY 2019-20
1	Preparation of SLIP and SAAP	NA	NA	INCLUDED IN SCOPE OF WORK OF PDMC	Total allocation for preparation of SLIP & SAAP is 2.25 cr., Since current year SLIP & SAAP prepared in house therefore amount is adjusted in scope of PDMC. The documents will be prepared by PDMC from next FY.	
2	PDMC	42.83	9.51	13.42	9.95	42.83
3	State PMU & City PMU	31.23	4.34	8.97	8.96	8.96
5	Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)	NA	NA	NA	NA	NA
6	Capacity Building and Training	NA	NA	NA	NA	NA
	- CCBP, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA
	- Others	NA	NA	NA	NA	NA
7	Reform implementation	NA	NA	NA	NA	NA
8	Others	6.72	1.08	1.88	1.88	1.88
	Total	**80.78**	**14.93**	**24.27**	**20.79**	**20.79**

- **Do projects proposed in the SAAP include O&M for at least five years? What is the nature of O&M?**

  Yes, all projects under water supply, sewerage & septage management, Green spaces proposed in SAAP for the entire mission period have made provisions of O&M cost for 5 years for smooth roll out of projects. It has been planned to incorporate necessary provisions of O&M in the respective DPRs and Contract documents.

- **How O&M expenditures are propose to be funded by ULBs/ parastatal?**

  The operation and maintenance of the projects proposed under the Mission will be done by the concerned ULBs and the cost of O&M shall be funded through user-charges collected by the respective ULBs

  O&M cost of the assets created, after the Defect Liability Period (DLP) are proposed through recovery of user charges, uniform rise in tariff structure, reduction of losses. If there will be any gap in recovery of user charges, cost shall be borne by the ULBs from the departmental budget/14th Finance Commission grants and other financial options like PPP etc.

- **Is it by way of levy of user charges or other revenue streams?**

  It is proposed that cost of O&M shall be recovered by way of user charges, which will be collected by the respective ULB. However, in the initial phase until the full roll out, the cost of O&M is proposed to be funded by the grants-in-aid provided to ULBs under various heads. O & M cost estimates have been prepared forming part of the DPRs and based on proposed Water Tariff, the revenue collection forecast has also been carried for Intermediate and Ultimate stage of the Schemes.

- **Has O&M cost been excluded from project cost for the purpose of funding?**

  Yes, for the purpose of calculation of the project cost, the O&M cost has been excluded as per the Guidelines of the Mission.

- **What kind of model been proposed by States/ULBs to fund the O&M? Please discuss.**

  The O&M cost of the proposed services under various projects concerning water supply, sewerage and septage etc. shall be funded by the respective ULB through user charges and dovetailing with funds available under other schemes as applicable. Additionally, PPP opportunities shall be explored to recover the user charges however, in the initial phase user charges may not be sufficient to fund the entire O&M cost for which innovative proposals like energy saving projects, reduction in NRW etc. will be considered.

- Is it through an appropriate cost recovery mechanism in order to make them self-reliant and cost-effective? How?

  Cost recovery mechanism shall be formulated while preparation of DPR and bid document. It will be an integral part of all projects proposed under the mission.

3.3 REFORM IMPLEMENTATION

- **Fill out the tables prescribed by the TCPO. What are the Reform type, steps and Target for 2017-18?**

Table 5.2: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2016 – 17

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	Apr to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
1	E Governance	1. Coverage with E-MASS (from the date of hosting the software)	24 months	Target to be achieved with in stipulated time				Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		Registration of Birth, Death and Marriage						
		Water & Sewerage Charges						
		Grievance Redressal						
		Property Tax						
		Advertisement Tax						
		Issuance of Licenses						
		Building Permissions						
		Mutations						
		Pay Roll						
		Pension and e-Procurement						
2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1. Establishment of Municipal Cadre	24 months					Under Progress. To be accomplished within prescribed timeline
		2. Cadre linked training						To be accomplished within

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	Apr to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
				Target to be achieved with in stipulated time				prescribed timeline
3	Augmenting double entry accounting	Appointment of internal auditor	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
4	Urban Planning and City Development Plans	1. Make a State level policy for implementation the parameters given the National Mission for Sustainable Habitat	24 months					Policy will be formulated within the timelines stipulated under the mission.
5	Devolution of Funds and functions	1. Implementation of SFC recommendations within timeline.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
6	Review of Buidling by-laws	1. State to formulate a policy and action plan for having a solar roof top in all buildings having an area greater than 500 square meters and all public buildings.	24 months					Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	Apr to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
		2. State to formulate a policy and action plan for having Rainwater harvesting structures in all commercial, public buildings and new buildings on plots of 300sq. meters and above.	24 months	Target to be achieved with in stipulated time				
7	Set-up financial intermediary at state level	1. Establish and operationalize financial intermediary- pool finance, access external funds, float municipal bonds.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline
8	Credit Rating	1. Complete the credit ratings of the ULBs.	24 months					To be accomplished within prescribed timeline
9	Energy and Water audit	1. Give incentives for green buildings (e.g. rebate in property tax or charges connected to building permission/ development charges).	24 months					

Table 5.3: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2017 – 18

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP					
				April to Sept. 2015	Oct 2015 to March 2016	April to Sept. 2016	Oct 2016 to March 2017	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018
1	E Governance	1. Personal staff management 2.Project management	36 months	Target to be achieved with in stipulated time					
2	Urban Planning and city development plant	1. Establish Urban Development Authorities	36 months						
3	Swach Bharat Mission	1. Elimination of ODF. 2. Waste Collection (100%) 3. Transportation of waste (100%) 4. Scientific disposal (100%) 5. The state will prepare the policy for right sizing the number of the municipal functionaries depending on, say , population of the ULB, generation of internal resources and expenditures on salaries.	36 months						

Table 5.4: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2018 – 19

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP							
				April to Sept. 2015	Oct 2015 to March 2016	April to Sept. 2016	Oct 2016 to March 2017	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018
1	Urban Planning and city development plant	1. Preparation of master plant using GIS	48 months	Target to be achieved with in stipulated time							

- **Fill out Table 5.5 (pg. 54) given in the AMRUT Guidelines. What is the outcome of the self-evaluation done for reporting progress on reform implementation in order to receive the 10% incentive?**

  Self- Evaluation for reporting progress on Reform Implementation will be submitted before 30th April 2017 as per the reform incentive claim deadlines.

- **Have any issues been identified during the review by HPSC on Reforms implementation? What are the issues?**

  No

- **Have these issues been considered while planning for reform implementation? How?**

  NA

3.4 ANNUAL CAPACITY BUILDING PLAN

Table 7.2.1: Fund requirement for Individual Capacity Building at ULB level

Sr. No	Name of ULB	Total numbers to be trained in the current financial year, department wise						Name of the Training Institution (s) identified	No. of Training Programmes to be conducted	Fund Reqd. in current FY (₹ in Lakhs)
		Elected Reps.	Finance Dept.	Engineering Dept.	Town Planning Dept.	Admin. Dept.	Total			
1	Raipur	0.00	4	9	12	0.00	25	i. State Administrative Academy ii. ASCI Hyderabad iii. ESCI Hyderabad iv. AIILSG, New Delhi	4 batches of 30 participants each to undergo 3 Modules of Training	45.19
2	Bilaspur	0.00	3	8	5	0.00	16			
3	Durg	0.00	4	5	8	0.00	17			
4	Bhilai	0.00	4	8	5	0.00	17			
5	Rajnand-gaon	0.00	3	5	0.00	0.00	8			
6	Korba	0.00	3	12	0.00	0.00	15			
7	Raigarh	0.00	3	4	0.00	0.00	7			
8	Ambika-pur	0.00	3	5	0.00	0.00	8			
9	Jagdalpur	0.00	3	4	0.00	0.00	7			
	Total	**0.00**	**30**	**60**	**30**	**0**	**120**			**45.19**

- **Is the State willing to revise their town planning laws and rules to include land pooling?**

  Yes, required revisions are partially completed, detailed revision will be completed within reform implementation timeline.

- **List of ULBs willing to have a credit rating done as the first step to issue bonds?**

  Credit Rating of 2 cities namely Raipur and Bhilai is done and CR of rest 7 AMRUT cities is going on and will be completed till 31st March, 2017.

- **Is the State willing to integrate all work done in GIS in order to make GIS useful for decision-making in ULBs?**

  Yes, state completed GIS mapping of all mission cities under GIS based PTIS and BPMS project. All the 9 ULBs have 83 layered GIS base map. GIS Master Plan is being prepared and is currently being used in decision making. State is planning to develop an IT & GIS based system for decision making.

- **Is the State willing to take assistance for using land as a fiscal tool in ULBs?**

  Yes, state is exploring the possibility of using land as fiscal tool in ULBs. Raipur Smart City Proposal having provision of land incentivizing.

- **Does the State require assistance to professionalize the municipal cadre?**

  Yes, a Regional Institute of Urban Management is approved in principle by MoUD. Grant as well sanction awaited from GoI.

- **Does the State require assistance to reduce non-revenue water in ULBs?**

  Proposed in SAAP under reform implementation plan.

- **Does the State require assistance to improve property tax assessment and collections in ULBs?**
  Yes. State partially completed the GIS based Property Tax Evaluation project in all the mission cities. For proper implementation of the project, state needs support from GoI.
- **Does the State require assistance to establish a financial intermediary?**
  State has initiated procedures to establish a financial intermediary.
- **Any other capacity assistance to implement the AMRUT Reform Agenda as set out in these Guidelines?**
  AMMU has been established for the same. Additional fund required for convergence of Digital India.
- **What is the physical and financial Progress of capacity development at state level?**

Physical Progress of capacity development at state level

State Urban Development Agency (SUDA), Chhattisgarh has been signed MoU with three institutes which have been empaneled by MoUD

1. Engineering Staff College of India (ESCI), Hyderabad
2. All India Institutes of Local Self Government (AIILSG), New Delhi
3. Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad

Sr. No	Name of Department and Position	Q 1 (2016-17 FY)		Q 2 (2016-17 FY)		Q 3 (2016-17 FY)		Q 4 (2016-17 FY)		Total Achieved in 2016-17 FY
		Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	Target	Achieved	
1	Elected Representative	0	0	0	0	53	53	58		111
2	Finance Department	0	0	0	0	84	84	0		84
3	Engineering Department	0	0	0	0	60	60	0		60
4	Town Planning	0	0	0	0	28	28	0		28
5	Administrative Department	0	0	0	0	85	85	0		85
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**310**	**310**	**58**		**368**

- **Do you feel that there is a need to include any other category of official, new department or module?**

  Yes, expertise required for cadre linked training.

- **What are the issues that are been identified during the review?**

  NA

- **Have the activities in your current year Capacity Building Plan – training, exposure visits (ULB staff and elected representatives), seminars/workshops, etc. – been vetted/approved by NIUA?**

  Proposal being submitted.

- **What is the present institutional capacity in the ULBs of the state; have the RPMC, UMC, etc. been appointed? Are there other PMUs, PIUs, etc. which are still operational?**

  State Mission Management Unit & City Mission Management Units have been established.

- **What has been the progress during the previous year/s in institutional capacity building, especially but not only in the seven areas that are mentioned in the AMRUT Guidelines? (p. 67)**

  1. **Empanelled handholding agencies and/or consulting firms for preparation of Smart City Proposal for the Smart Cities selection competition.**
  2. **Empanelled handholding agencies and/or consulting firms for complete end-to-end assistance in AMRUT for the preparation for SLIP, Project Development (e.g. design, estimation) and Management.**
  3. **Established AMMU for assisting in implementing reform agenda focusing on outcomes, as given in AMRUT Reforms.**
  4. **Firms selected for credit rating for all AMRUT towns**
  5. **Developed multi-layer GIS maps connected to data (attribute tables) in order to enable ULBs to use GIS for decision-making.**
  6. **AMMU selected to assist the State/ULBs to revise Laws and Rules (e.g. land pooling) for implementing the AMRUT Reform/Agenda.**

- **Attach the Quarterly Score Cards on p. 73 of the Mission Guidelines.**

  Not eligible as implementation is not there.

- **Have those issues been addressed? How?**

  NA

A. A&OE

Table 4: Broad proposed allocations for administrative and other expenses

Sr. No	Items proposed for A&OE	Total Allocation	Committed Expenditure from previous year (if any)	Proposed spending for Current Financial year (2017-18)	Balance to Carry Forward	
					FY 2018-19	FY 2019-20
1	Preparation of SLIP and SAAP	NA	NA	INCLUDED IN SCOPE OF WORK OF PDMC	Total allocation for preparation of SLIP & SAAP is 2.25 cr. The documents are being prepared by PDMC.	
2	PDMC	42.83	9.51	13.42	9.95	42.83
3	State PMU & City PMU	31.23	4.34	8.97	8.96	8.96
5	Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)	NA	NA	NA	NA	NA
6	Capacity Building and Training	NA	NA	NA	NA	NA
	- CCBP, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA
	- Others	NA	NA	NA	NA	NA
7	Reform implementation	NA	NA	NA	NA	NA
8	Others	6.72	1.08	1.88	1.88	1.88
	Total	80.78	14.93	24.27	20.79	20.79

- **What is the committed expenditure from previous year?**

  RS. 15.69 Cr is the committed expenditure from previous 2 years.

- **What are the issues that are being identified during the review?**

  A&OE received is not sufficient. Total A&OE allocation for Mission Period is Rs. 80.78 crore and till date state has received only 2.25Cr. Since it is not clear how state will get its committed A&OE fund that is why proper mission planning and implementation is a real challenge.

- **Have the A&OE fund used only for admissible components?**

  Yes. As per table 4.4. of AMRUT Guidelines.

- **How the ULB/State wants to carry out the implementation of the projects, (establishment of IRMA/PDMC/SMMU/CMMU)?**

  Team appointed for monitoring and construction supervision under PDMC is inadequate. It needs to be augmented at all ULB level with field staff. Moreover, a dedicated team for PMC could be deployed at each ULB level for better implementation. Also additional designed for achieving the targets set out in SAAP may kindly be allowed.

B. FINANCING OF PROJECTS

- **What is the State contribution to the SAAP? (should be greater than 20 percent, Para 7.4 of AMRUT Guidelines)**

  Total allocation proposed under SAAP for the remaining mission period (2017 – 20) is Rs. 878.99 Cr. Out of which central government's contribution for Chhattisgarh is Rs.424.70 crore. The state's contribution to the SAAP for the remaining mission period 2017 – 20 is Rs. 272.57 cr. This is 31% of the total allocation (Rs. 878.99 cr.) made under SAAP for the current year. ULB share in the SAAP for remaining mission period is Rs. 181.71 cr. State's share will be 40% in case of cities with population above 10 lakhs and 30% in case of cities with population below 10 lakhs as per AMRUT Guidelines.

- **How the residual financing (over and above Central Government share) is shared between the States, ULBs?**

  The financial support from the central government for projects proposed under AMRUT is in line with the funding pattern stipulated in the mission guidelines i.e. 1/3rd for cities with population above 10 lakhs and ½ for cities with population below 10 lakhs. The state share will be 40% in case of cities with population above 10 lakhs and 30% for cities with population below 10 lakhs.

- **Fill out Table 3.3 at pg 44 of AMRUT Guidelines. Has any other sources identified by the State/ULB (e.g. PPP, market borrowing)? Please discuss.**

  Assistance from GoI is required to mobilize foreign funding.

Table 3.3: Share of investments for all sectors (ULB wise) FY 2017 – 20

Name of ULB	Centre	State			ULB			Convergence	Others (e.g. incentive)	Total
		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total			
Raipur	29.91	0.0	35.70	35.70	0.0	23.80	23.80	-	-	89.40
Bilaspur	70.94	0.0	42.56	42.56	0.0	28.38	28.38	-	-	141.88
Durg	52.04	0.0	31.22	31.22	0.0	20.81	20.81	-	-	104.07
Bhilai	35.07	0.0	21.04	21.04	0.0	14.03	14.03	-	-	70.14
Rajnandgaon	86.61	0.0	51.97	51.97	0.0	34.64	34.64	-	-	173.22
Korba	40.61	0.0	24.37	24.37	0.0	16.24	16.24	-	-	81.22
Raigarh	42.16	0.0	25.30	25.30	0.0	16.86	16.86	-	-	84.32
Ambikapur	32.12	0.0	19.27	19.27	0.0	12.85	12.85	-	-	64.24
Jagdalpur	35.25	0.0	21.15	21.15	0.0	14.10	14.10	-	-	70.50
Total	**424.70**	**0.00**	**272.57**	**272.57**	**0.0**	**181.71**	**181.71**	-	-	**878.99**

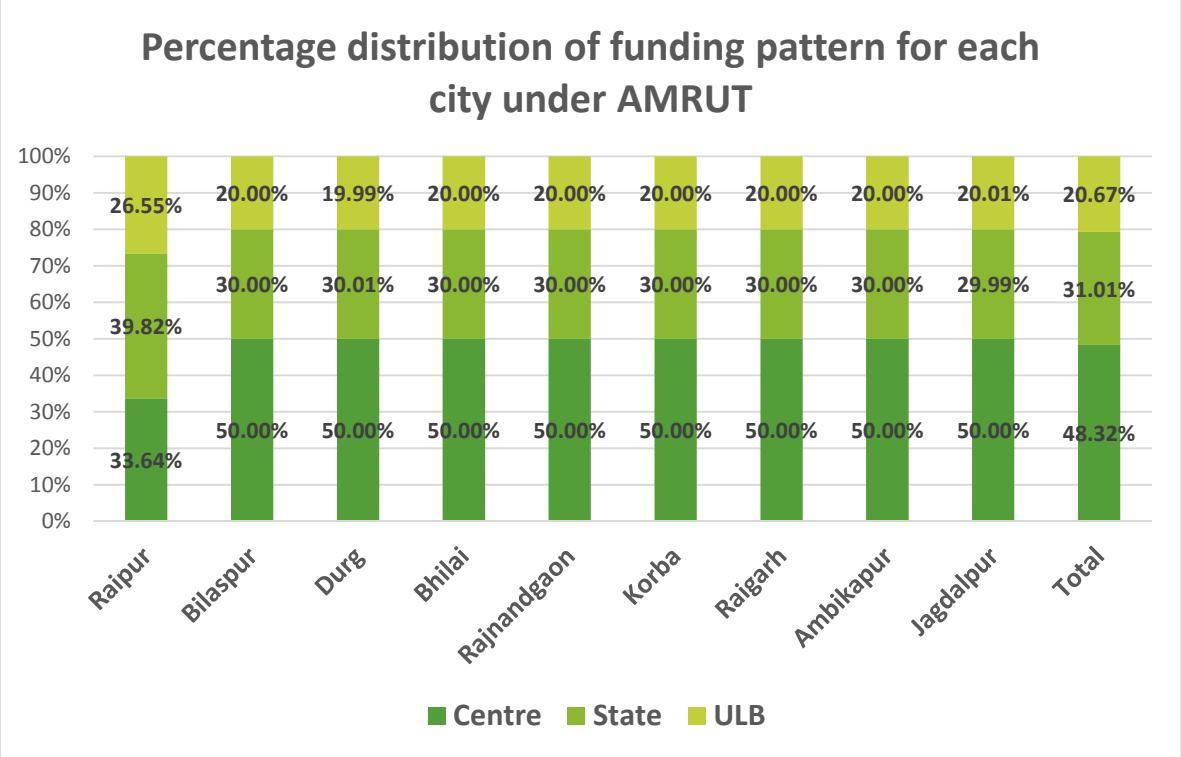

- **Whether complete project cost is linked with revenue sources in SAAP? Please describe?**
  Yes, ULB share is funded through FFC and self-revenue.
- **Has projects been dovetailed with other sectoral and financial programme of the Centre and State Governments?**
  Yes, SBM/ State Sponsored Scheme/14thFC

- **Has States/UTs explored the possibility of using Public Private Partnerships (PPP), as a preferred execution model? Please discuss.**

  While formulating the detailed Project reports (DPRs), PPP options shall be explored for O&M of projects under various sectors.

- **Are PPP options included appropriate Service Level Agreements (SLAs) which may lead to the People Public Private Partnership (PPPP) model? How?**

  Service Level Agreements will be included at DPR & RFP stage as per SLIP & SAAP.

  PPPP model prepared for open space/ Parks/ Green spaces/ Lakes etc.

CHAPTER 4: TABLES:

Table 1.1(a): Breakup of Total MoUD Allocation in AMRUT FY:-2017-20 (Amount in Cr.)

Total Central funds allocated to State	Allocation of Central funds for A&OE	Allocation of funds for AMRUT (Central share)	Multiply col. 3 by 3 for AMRUT on col. 4 (project proposal to be three- times the annual allocation - CA)	Add equal (col. 4) State/UL B share	Total AMRUT annual size (cols.2+4+5)
1	2	3	4	5	6
175.54	33.98	141.57	424.70	454.28	878.99

Table 1.2.2: Abstract-Sector Wise Proposed Total Project Fund and Sharing Pattern for FY 2015 – 20 (Amount in Cr.)

Sr. No	Sector	Centre	State		ULB		Total
		Mission	Others	Total	Others	Total	
1	Water Supply	822.33	530.75	530.75	353.83	353.83	1706.91
2	Sewerage and Septage Management	168.61	167.30	167.30	111.53	111.53	447.44
3	Others (Green Spaces & Parks)	18.80	11.76	11.76	7.84	7.84	38.40
	Sub Total	1009.74	709.81	709.81	473.20	473.20	2192.75
	Grand Total	**1009.74**	**709.81**	**709.81**	**473.20**	**473.20**	**2192.75**

Table 1.3: Abstract-Use of Funds on Projects: On Going and New (Amount in Rs. Cr.) **For the Financial Year 2016-2017**

Sr. No	Sector	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year (2015 - 2016 & 2016-17)							Proposed Spending during remaining Mission Period (2017 - 2020)							Balance Carry Forward for Next Financial Years						
			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB			Centre	State			ULB		
				14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total		14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total
1	Water Supply	1706.91	404.22	0.0	262.13	262.13	0.0	174.76	174.76	418.11	0.0	268.61	268.61	0.0	179.08	179.08	-	-	-	-	-	-	-
2	Sewerage and Septage Management	447.44	166.61	0.0	166.10	166.10	0.0	110.73	110.73	2.00	0.0	1.20	1.20	0.0	0.80	0.80	-	-	-	-	-	-	-
3	Others (Green Spaces & Parks)	38.40	14.21	0.0	9.00	9.00	0.0	6.00	6.00	4.60	0.0	2.76	2.76	0.0	1.84	1.84	-	-	-	-	-	-	-
	Grand Total	**2192.75**	**585.04**	**0.00**	**437.23**	**437.23**	**0.00**	**291.49**	**291.49**	**424.70**	**0.00**	**272.57**	**272.57**	**0.00**	**181.71**	**181.71**	-	-	-	-	-	-	-

Table 1.4: Abstract-Plan for Achieving Service Level Benchmark

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
Water Supply	1706.91	1. Household level coverage of direct water supply connections	45.12	-	-	-	-	78.00	100.0
		2. Per capita quantum of water supplied	98.16	-	-	-	-	120.00	135.00
		3. Quality of water supplied	81.14	-	-	-	-	97.40	100.00
Sewerage and Septage Management	447.44	4. Coverage of latrines (individual or community)	69.92	-	-	95.20	100.00	100.00	100.00
		5. Coverage of sewerage network services	4.67	-	-	6.69	33.50	78.80	100.00
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	6.67	-	-	7.30	40.30	85.70	100.00
		7. Efficiency in treatment	8.33	-	-	-	26.89	87.34	100.00
Others (Green Spaces & Parks)	38.40	**No SLB study of parks and green spaces has been conducted yet. However at least one park in each mission city will be developed every year.**							

Table 3.2 : SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	186.75	330.65	7.00	524.40
2	Bilaspur	304.36	21.79	6.00	332.15
3	Durg	145.00	15.00	3.20	163.20
4	Bhilai	242.73	20.00	4.00	266.73
5	Rajnandgaon	223.68	14.00	4.00	241.68
6	Korba	229.99	18.00	4.00	251.99
7	Raigarh	148.00	10.00	3.20	161.20
8	Ambikapur	106.98	8.00	4.00	118.98
9	Jagdalpur	119.42	10.00	3.00	132.42
	TOTAL	**1706.91**	**447.44**	**38.40**	**2192.75**
Total Project Investments					**2192.75**
A&OE					**80.78**
Grand Total					**2273.53**

NOTE: A&OE component has been calculated as 8% of the total Central allocation during the Mission Period

Table 3.2 (a): SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2016

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	10.00	2.40	61.40
2	Bilaspur	81.84	21.79	1.60	105.23
3	Durg	35.67	15.00	0.86	51.53
4	Bhilai	77.04	20.00	0.86	97.90
5	Rajnandgaon	26.94	12.00	0.86	39.80
6	Korba	67.12	18.00	0.86	85.98
7	Raigarh	32.15	10.00	0.86	43.01
8	Ambikapur	46.16	6.00	0.86	53.02
9	Jagdalpur	24.67	10.00	0.86	35.53
	TOTAL	**440.59**	**122.79**	**10.02**	**573.40**
Total Project Investments					**573.40**
A&OE					**8.98**
Grand Total					**582.38**

Table 3.2 (b) : SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2016-2017

Sr. No	Name of ULB	Water Supply	Sewerage and Septage Management	Others (Green Spaces & Parks)	Total
1	Raipur	49.00	320.65	3.95	373.60
2	Bilaspur	81.85	0.00	3.20	85.05
3	Durg	5.88	0.00	1.72	7.60
4	Bhilai	96.97	0.00	1.72	98.69
5	Rajnandgaon	26.94	0.00	1.72	28.66
6	Korba	83.07	0.00	1.72	84.79
7	Raigarh	32.15	0.00	1.72	33.87
8	Ambikapur	0.00	0.00	1.72	1.72
9	Jagdalpur	24.67	0.00	1.72	26.39
	TOTAL	**400.53**	**320.65**	**19.19**	**740.365**
Total Project Investments					**740.365**
A&OE					**8.96**
Grand Total					**749.325**

Table 3.2 (c) : SAAP - Sector Wise Breakup of Consolidated Investments for all ULBs in the State (Amount in Cr.) For the Financial Year 2017-2020

Sr. No	Name of ULB	Water Supply		Sewerage and Septage Management		Others (Green Spaces & Parks)		Total	
		Amount	No of projects	Amount	No of projects	Amount	No of projects	Amount	No of projects
1	Raipur	88.75	1	0.00	-	0.65	3	89.40	4
2	Bilaspur	140.68	2	0.00	-	1.20	3	141.88	5
3	Durg	103.45	1	0.00	-	0.62	3	104.07	4
4	Bhilai	68.72	1	0.00	-	1.42	3	70.14	4
5	Rajnandgaon	169.80	1	2.00	1	1.42	3	173.22	5
6	Korba	79.80	1	0.00	-	1.42	3	81.22	4
7	Raigarh	83.70	1	0.00	-	0.62	3	84.32	4
8	Ambikapur	60.82	1	2.00	1	1.42	3	64.24	5
9	Jagdalpur	70.08	1	0.00	-	0.42	3	70.50	4
	TOTAL	865.80	10	4.00	2	9.19	27	878.99	39
Total Project Investments								878.99	
A&OE (80.78-8.98-8.96)								62.84	
Grand Total								941.83	

Table 3.4: SAAP - Year Wise Share of Investments for All Sectors (ULB Wise) for remaining mission period FY 2016 - 2017

Sr. No	Name of ULB	Total Project Investment	Committed Expenditure (if any) from Previous year 2015-16 & 2016-17							Proposed Spending during remaining Mission Period 2017 - 2020							Balance Carry Forward for Next Financial Years						
				State			ULB				State			ULB				State				ULB		
			Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	Centre	14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total
1	Raipur	**524.40**	145.66	0.0	173.61	173.61	0.0	115.74	115.74	29.91	0.0	35.70	35.70	0.0	23.80	23.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Bilaspur	**332.15**	95.14	0.0	57.08	57.08	0.0	38.06	38.06	70.94	0.0	42.56	42.56	0.0	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Durg	**163.20**	29.57	0.0	17.74	17.74	0.0	11.83	11.83	52.04	0.0	31.22	31.22	0.0	20.81	20.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Bhilai	**266.73**	98.30	0.0	58.98	58.98	0.0	39.32	39.32	35.07	0.0	21.04	21.04	0.0	14.03	14.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Rajnandgaon	**241.68**	34.23	0.0	20.54	20.54	0.0	13.69	13.69	86.61	0.0	51.97	51.97	0.0	34.64	34.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Korba	**251.99**	85.39	0.0	51.23	51.23	0.0	34.15	34.15	40.61	0.0	24.37	24.37	0.0	16.24	16.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Raigarh	**161.20**	38.44	0.0	23.06	23.06	0.0	15.38	15.38	42.16	0.0	25.30	25.30	0.0	16.86	16.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Ambikapur	**118.98**	27.37	0.0	16.4	16.42	0.0	10.95	10.95	32.12	0.0	19.27	19.27	0.0	12.85	12.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Jagdalpur	**132.42**	30.96	0.0	18.58	18.58	0.0	12.38	12.38	35.25	0.0	21.15	21.15	0.0	14.10	14.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grand Total		**2192.75**	**585.04**	**0.00**	**437.23**	**437.23**	**0.00**	**291.49**	**291.49**	**424.70**	**0.00**	**272.57**	**272.57**	**0.00**	**181.71**	**181.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Table 3.1: Master Plan of all projects details to achieve universal coverage during the current Mission period based on Table 2.1 (Amount in Cr.) For the Financial Year 2015-2020

Sr. No	Name of ULB (water supply and sewerage)	Total number of projects to achieve universal coverage	Estimated	Number of years to achieve universal coverage
1	Raipur	8	517.40	5
2	Bilaspur	4	326.15	5
3	Durg	2	160.00	5
4	Bhilai	8	262.73	5
5	Rajnandgaon	3	237.68	5
6	Korba	9	247.99	5
7	Raigarh	2	158.00	5
8	Ambikapur	3	114.98	5
9	Jagdalpur	2	129.42	5
Grand Total		**41**	**2154.35**	**5**

Table 3.5: SAAP – State level Plan for Achieving Service Level Benchmarks

Proposed Priority Projects	Total Project Cost	Indicator	Baseline	Annual Targets based on Master Plan (Increment from the Baseline Value)					
				FY 2016		FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020
				H1	H2				
Water Supply	**1706.91**	1. Household level coverage of direct water supply connections	**45.12**	-	-	-	-	**78.00**	**100.0**
		2. Per capita quantum of water supplied	**98.16**	-	-	-	-	**120.00**	**135.00**
		3. Quality of water supplied	**81.14**	-	-	-	-	**97.40**	**100.00**
Sewerage and Septage Management	**447.44**	4. Coverage of latrines (individual or community)	**69.92**	-	-	**95.20**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
		5. Coverage of sewerage network services	**4.67**	-	-	**6.69**	**33.50**	**78.80**	**100.00**
		6. Efficiency of Collection of Sewerage	**6.67**	-	-	**7.30**	**40.30**	**85.70**	**100.00**
		7. Efficiency in treatment	**8.33**	-	-	-	**26.89**	**87.34**	**100.00**
Others (Green Spaces & Parks)	**38.40**	**No SLB study of parks and green spaces has been conducted yet. However at least one park in each mission city will be developed every year.**							

Table 4: SAAP - Broad Proposed Allocations for Administrative and Other Expenses (Amount in Cr.)

Sr. No	Items proposed for A&OE	Total Allocation	Committed Expenditure from previous year (if any)	Proposed spending for Current Financial year 2017-18	Balance to Carry Forward	
					FY 2018 - 2019	FY 2019-FY 2020
1	**Preparation of SLIP and SAAP**	NA	NA	INCLUDED IN SCOPE OF WORK OF PDMC	Total allocation for preparation of SLIP & SAAP is 2.25 cr. The documents are being prepared by PDMC.	
2	**PDMC**	42.83	9.51	13.42	9.95	9.95
3	**State PMU & City PMU**	31.23	4.34	8.97	8.96	8.96
4	**Publications (e-Newsletter, guidelines, brochures etc.)**	NA	NA	NA	NA	NA
5	**Capacity Building and Training - CCBP, if applicable - Others**	NA	NA	NA	NA	NA
6	**Reform implementation**	NA	NA	NA	NA	NA
7	**Others**	6.72	1.08	1.88	1.88	1.88
	Total	**80.78**	**14.93**	**24.27**	**20.79**	**20.79**

Table 5.2: Reforms Type, Steps and Target for AMRUT Cities FY: 2016 - 2017

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP				Remarks
				Oct. 2015 to Mar. 2016	April to Sept2016	Oct. 2016 to Mar. 2017	Apr. to Sep. 2017	
1	E Governance	1. Coverage with E-MASS (from the date of hosting the software)	24 months	Target to be achieved with in stipulated time				Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		Registration of Birth, Death and Marriage						
		Water & Sewerage Charges						
		Grievance Redressal						
		Property Tax						
		Advertisement Tax						
		Issuance of Licenses						
		Building Permissions						
		Mutations						
		Pay Roll						
		Pension and e- Procurement						
2	Constitution and professionalization of municipal cadre	1. Establishment of Municipal Cadre	24 months					Under Progress. To be accomplished within prescribed timeline
		2. Cadre linked training						To be accomplished within prescribed timeline

3	Augmenting double entry accounting	Appointment of internal auditor	24 months		Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
4	Urban Planning and City Development Plans	1. Make a State level policy for implementation the parameters given the National Mission for Sustainable Habitat	24 months		Policy will be formulated within the timelines stipulated under the mission.
5	Devolution of Funds and functions	1. Implementation of SFC recommendations within timeline.	24 months		Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
6	Review of Building by-laws	1. State to formulate a policy and action plan for having a solar roof top in all buildings having an area greater than 500 square meters and all public buildings.	24 months		Partially achieved. To be accomplished within prescribed timeline
		2. State to formulate a policy and action plan for having Rainwater harvesting structures in all commercial, public buildings and new buildings on plots of 300sq. meters and above.	24 months		
7	Set-up financial intermediary at state level	1. Establish and operationalize financial intermediary- pool finance, access external funds, float municipal bonds.	24 months		To be accomplished within prescribed timeline
8	Credit Rating	1. Complete the credit ratings of the ULBs.	24 months		To be accomplished within prescribed timeline

9	Energy and Water audit	1. Give incentives for green buildings (e.g. rebate in property tax or charges connected to building permission/ development charges).	24 months		

Table 5.3: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2017 – 18

Sr. No.	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP					
				April to Sept. 2015	Oct 2015 to March 2016	April to Sept. 2016	Oct 2016 to March 2017	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018
1	E Governance	1. Personal staff management 2.Project management	36 months	Target to be achieved with in stipulated time					
2	Urban Planning and city development plant	1. Establish Urban Development Authorities	36 months						

Sr. No.	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP					
				April to Sept. 2015	Oct 2015 to March 2016	April to Sept. 2016	Oct 2016 to March 2017	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018
3	Swach Bharat Mission	1. Elimination of ODF. 2. Waste Collection (100%) 3. Transportation of waste (100%) 4. Scientific disposal (100%) 5. The state will prepare the policy for right sizing the number of the municipal functionaries depending on, say , population of the ULB, generation of internal resources and expenditures on salaries.	36 months						

Table 5.4: Reform Type, Steps and Target for AMRUT Cities in Chhattisgarh FY 2018 – 19

Sr. No	Type	Steps	Implementation Timeline	Target to be set by states in SAAP							
				April to Sept. 2015	Oct 2015 to March 2016	April to Sept. 2016	Oct 2016 to March 2017	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018	April to Sept. 2017	Oct 2017 to March 2018
1	Urban Planning and city development plant	1. Preparation of master plant using GIS	48 months	Target to be achieved with in stipulated time							

Table 7.2.1: Fund Requirement for Individual Capacity Building at ULB level

Sr. No	Name of ULB	Total numbers to be trained in the current financial year, department wise						Name of the Training Institution (s) identified	No. of Training Programmes to be conducted	Fund Reqd. in current FY (₹ in Lakhs)
		Elected Reps.	Finance Dept.	Engineering Dept.	Town Planning Dept.	Admin. Dept.	Total			
1	Raipur	0.00	4	9	12	0.00	25	i. State Administrative Academy ii. ASCI Hyderabad iii. ESCI Hyderabad iv. AIILSG, New Delhi	4 batches of 30 participants each to undergo 3 Modules of Training	45.19
2	Bilaspur	0.00	3	8	5	0.00	16			
3	Durg	0.00	4	5	8	0.00	17			
4	Bhilai	0.00	4	8	5	0.00	17			
5	Rajnandgaon	0.00	3	5	0.00	0.00	8			
6	Korba	0.00	3	12	0.00	0.00	15			
7	Raigarh	0.00	3	4	0.00	0.00	7			
8	Ambikapur	0.00	3	5	0.00	0.00	8			
9	Jagdalpur	0.00	3	4	0.00	0.00	7			
	Total	**0.00**	**30**	**60**	**30**	**0**	**120**			**45.19**

Table 3.3: ULB Wise Source of Funds for All Sectors (Amount in Cr.) For the Financial Year 2017-20

Sr. No	Name of ULB	Centre	State			ULB			Total
			14th FC	Others	Total	14th FC	Others	Total	
1	Raipur	29.91	0.0	35.70	35.70	0.0	23.80	23.80	89.40
2	Bilaspur	70.94	0.0	42.56	42.56	0.0	28.38	28.38	141.88
3	Durg	52.04	0.0	31.22	31.22	0.0	20.81	20.81	104.07
4	Bhilai	35.07	0.0	21.04	21.04	0.0	14.03	14.03	70.14
5	Rajnandgaon	86.61	0.0	51.97	51.97	0.0	34.64	34.64	173.22
6	Korba	40.61	0.0	24.37	24.37	0.0	16.24	16.24	81.22
7	Raigarh	42.16	0.0	25.30	25.30	0.0	16.86	16.86	84.32
8	Ambikapur	32.12	0.0	19.27	19.27	0.0	12.85	12.85	64.24
9	Jagdalpur	35.25	0.0	21.15	21.15	0.0	14.10	14.10	70.50
	Total	**424.70**	**0.00**	**272.57**	**272.57**	0.0	**181.71**	**181.71**	**878.99**

Stakeholder Consultation

Stakeholder Consultation

कार्यालय
सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र (छ.ग.)
आकाशवाणी के पास राजभवन मार्ग
सिविल लाईन, रायपुर - 0771-2432909

कार्यालय सांसद लोकसभा रायपुर

विषय :– निकास में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूमेंट प्लॉन (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :– आयुक्त नगर निगम रायपुर का पत्र क्र./8049/दिनांक 06.10.2015।

मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत राशि रू. 688.68 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **पेय जल प्रदाय** :– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रू. 147.60 करोड़ रू. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में वर्तमान में जुड़े 07 गांवों एवं छूटे स्थलों में नई पाईप लाईन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा सॉफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. **सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमैंट** – अंडरग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सैप्टेज के उपचार के लिए सैप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर. तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर. के अनुसार राशि रू. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3. **हरित स्थल एवं पार्क** :– नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रू. 12.00 करोड़ की प्रावधान किया गया है।

4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि** :– मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले REFORM समय सीमा में पूर्ण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39 करोड़ आगामी वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार

कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण HPSC द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलत घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त क्रमांक– 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्युनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है.

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

रमेश बैस'
सांसद
लोक सभा रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)
विकास भवन नेहरू चौक, बिलासपुर
फोन नं. 07752-222642 फैक्स नं. 07752-413888
Email- commissionerbilaspur@yahoo.com website-www.bmcbilaspur.com

योजना का संक्षिप्त विवरण

विषय :- नगर निगम बिलासपुर द्वारा मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड रुपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. **पेयजल प्रदाय** – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रुपये 245.53 करोड रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहो में अंतराष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये खारंग जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एमएम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डीआई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा। 77 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र दोमुहानी बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पंपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लंबाई 35.12 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्य की मानिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
2. **सीवरेज** – सीवरेज की वर्तमान चलित योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेज की सुविधा प्राप्त होगी। वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेज पाईप लाईन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इस हेतु राशि रू. 16.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की समयसीमा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई।

3. सेप्टेज मैनजमेंट – अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रूपये 5.47 करोड का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 2 नग सीवरेज सक्शन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 3 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ–साथ कुछ कॉलोनी जिनका ग्राउंड लेवल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेज से जुडना संभव नहीं है, जिनमें सेप्टीक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है।

4. **हरित स्थल एवं पार्क** – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रूपये 8.00 करोड की परियोजना सम्मिलित की गई है।

5. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि** – मिशन अमृत को दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये 3.39 करोड़ आगामी तीन वर्षो में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षो के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

अनुशंसित

लखन लाल साहू
सांसद
लोकसभा क्षेत्र, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
नोडल अधिकारी, अमृत मिशन
नगर पालिक निगम
बिलासपुर (छ.ग.)

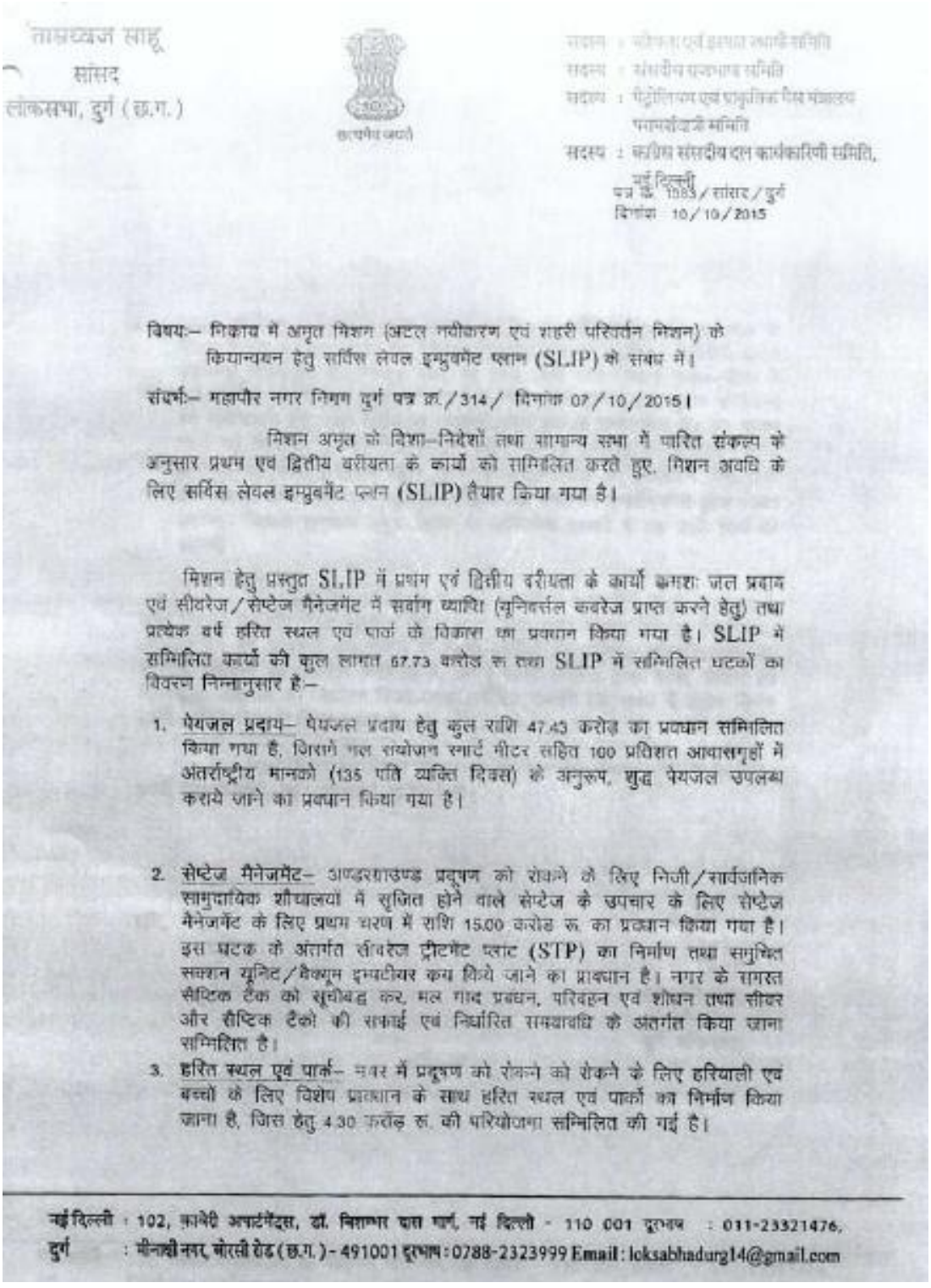

ताम्रध्वज साहू
सांसद
लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)

सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति
सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति
सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
परामर्शदात्री समिति
सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति,
नई दिल्ली

पत्र क्र. 1083 / सांसद / दुर्ग
दिनांक 10 / 10 / 2015

विषयः– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भः– महापौर नगर निगम दुर्ग पत्र क्र./314/ दिनांक 07/10/2015।

मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है–

1. <u>पेयजल प्रदाय</u>– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. <u>सेप्टेज मैनेजमेंट</u>– अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम चरण में राशि 15.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंकों की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।

3. <u>हरित स्थल एवं पार्क</u>– नगर में प्रदूषण को रोकने को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

नई दिल्ली : 102, कावेरी अपार्टमेंट्स, डॉ. बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : 011-23321476,
दुर्ग : मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड (छ.ग.) - 491001 दूरभाष : 0788-2323999 Email : loksabhadurg14@gmail.com

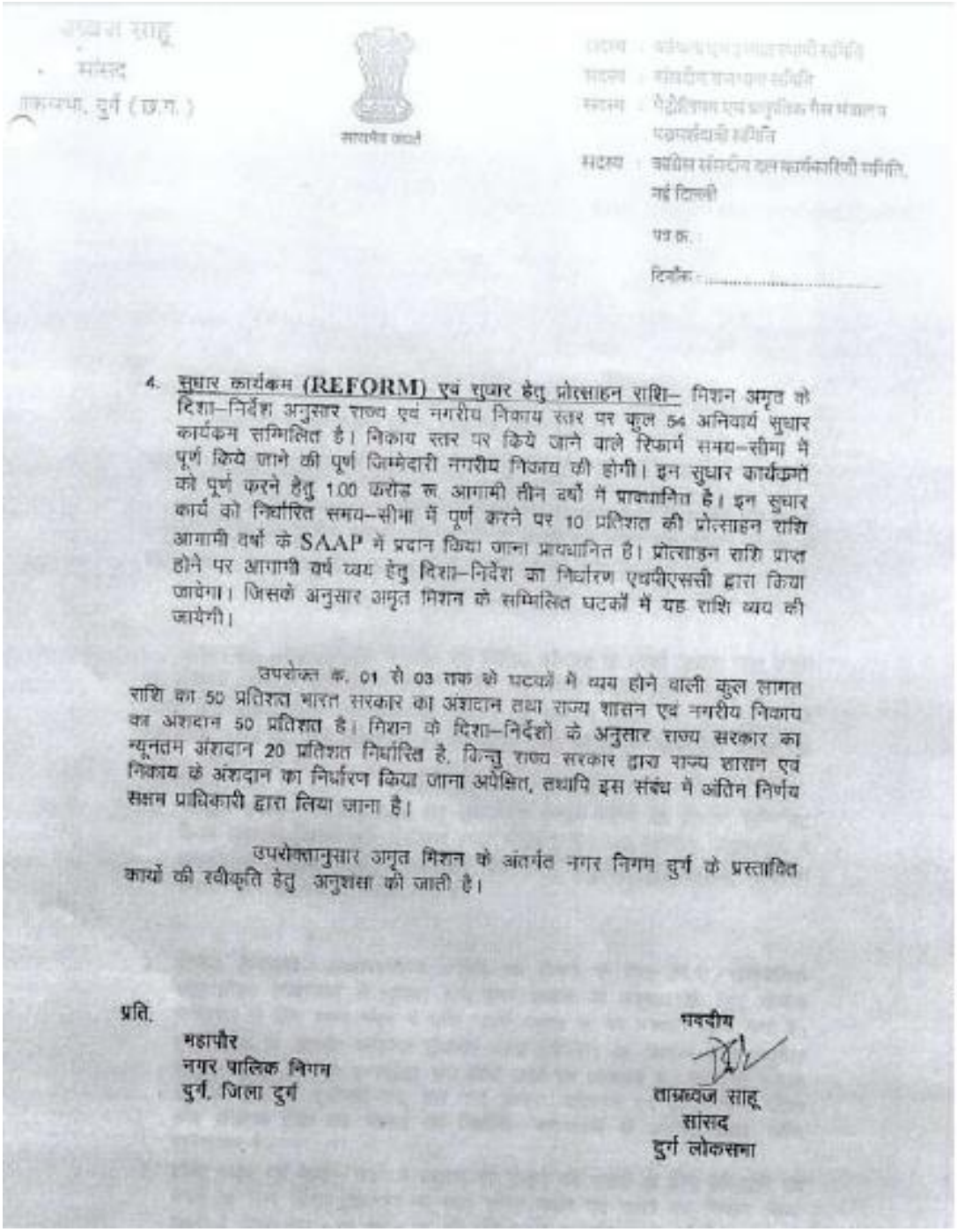

ताम्रध्वज साहू
सांसद
लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)

सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति
सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति
सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय परामर्शदात्री समिति
सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति, नई दिल्ली

पत्र क्र. :

दिनांक : ....

4. <u>सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि–</u> मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जायेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रति,
महापौर
नगर पालिक निगम
दुर्ग, जिला दुर्ग

भवदीय
(हस्ताक्षर)
ताम्रध्वज साहू
सांसद
दुर्ग लोकसभा

ताम्रध्वज साहू
सांसद
लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)

सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति
सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति
सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय परामर्शदात्री समिति
सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति, नई दिल्ली

पत्र क्र. :

दिनांक :..

4. <u>सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि–</u> मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एसपीएससी द्वारा किया जायेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रति,
महापौर
नगर पालिक निगम
दुर्ग, जिला दुर्ग

भवदीय

ताम्रध्वज साहू
सांसद
दुर्ग लोकसभा

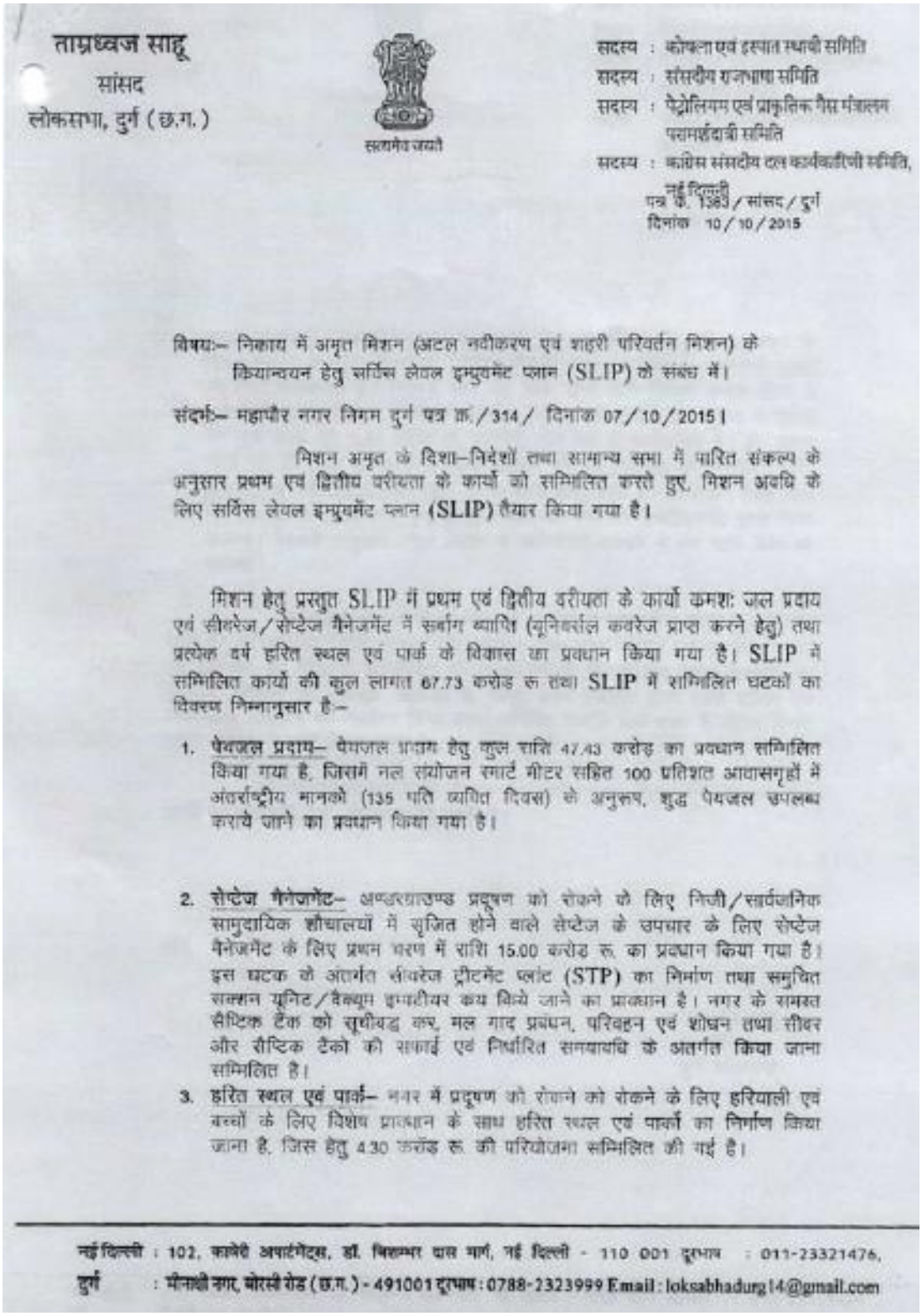

ताम्रध्वज साहू
सांसद
लोकसभा, दुर्ग (छ.ग.)

सत्यमेव जयते

सदस्य : कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति
सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति
सदस्य : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय परामर्शदात्री समिति
सदस्य : कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारिणी समिति, नई दिल्ली

पत्र क्र. 1363 / सांसद / दुर्ग
दिनांक 10 / 10 / 2015

विषयः– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भः– महापौर नगर निगम दुर्ग पत्र क्र./314/ दिनांक 07/10/2015।

मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान **(SLIP)** तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। **SLIP** में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रु तथा **SLIP** में शामिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है–

1. <u>पेयजल प्रदाय</u>– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. <u>सेप्टेज मैनेजमेंट</u>– अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम चरण में राशि 15.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट **(STP)** का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंको की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
3. <u>हरित स्थल एवं पार्क</u>– नगर में प्रदूषण को रोकने को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

नई दिल्ली : 102, कावेरी अपार्टमेंट्स, डॉ. बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 दूरभाष : 011-23321476,
दुर्ग : मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड (छ.ग.) - 491001 दूरभाष : 0788-2323999 Email : loksabhadurg14@gmail.com

सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है॥ प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार अमृत मिशन के अन्तर्गत नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

(डॉ. बंशीलाल महतो)

COMMISSIONER,
Municipal Corporation, Korba
Distt. - KORBA (C. G.)

कमलभान सिंह मरावी
संसद सदस्य (लोक सभा)
सरगुजा – छत्तीसगढ़
अध्यक्ष :
• भारतीय खाद्य निगम परामर्शदात्री समिति (छत्तीसगढ़)
सदस्य :
• रेल अभिलेख समिति
• रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
• जनजातीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समिति

सिंघाई कालोनी,
मैरीन ड्राइव की पास,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

ग्राम एवं पोस्ट जमगला विकास खण्ड,
लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
फोन : 09425264386

सत्यमेव जयते

विषय :– मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक 2498/लोनिवि/नपानि/2015–16 अम्बिकापुर दिनांक 09.10.2015

——0——

भारत सरकार के "मिशन अमृत" (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यान निर्माण के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रम के अनुपालन हेतु निम्नानुसार सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है :–

पेयजल आपूर्ति – नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रूपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु घुनघुटटा डेम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकवेल का निर्माण करते हुए 13.5 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु पावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु स्काडा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।

सेप्टेज मैनेजमेंट – भूजल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोकने हेतु निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 6.00 करोड़ का प्रावधान मिशन के SLIP में किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा कार्य हेतु आवश्यक मशीनरियों का क्रय किया जाना प्रावधानित है। सेप्टेज मैनेजमेंट कार्य के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक सेप्टिक टैंक को अधिकतम दो वर्ष में सफाई किये जाने एवं इस कार्य हेतु एकत्रित सीवेज का विधिवत् उपचार एवं पुनर्चक्रीकरण का कार्य किया जाना सम्मिलित है।

140, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001 • फोन : 09013669999

हरित स्थल एवं उद्यान – नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण स्तर को कम किये जाने के मूल उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में हरित स्थल एवं उद्यानों के विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु राशि रूपये 4.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर हरित स्थल एवं सर्वसुविधा युक्त उद्यानों का निर्माण जिसमें अहाता/फेरिंग, फुटपाथ, खेल उपकरण, व्यायाम उपकरण, प्रसाधन, पेयजल, कैंटिन आदि का यथोचित प्रावधान रखा गया है।

सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – अमृत मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले सुधार कार्यक्रमों समय–सीमा में निकाय द्वारा पूर्ण की जावेगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु योजनान्तर्गत राशि रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान आगामी तीन वर्षों हेतु रखा गया है। योजना के सुधार कार्यक्रमों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एसपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आवंटित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत का अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा पेयजल, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं उद्यानों के निर्माण तथा शासन द्वारा निर्धारित सुधार कार्यक्रमों के अनुपालन हेतु तैयार किये गये SLIP राशि रूपये 57.46 करोड़ के स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

14-10-15

(कमलभान सिंह मरावी)
सांसद, सरगुजा

अभिषेक सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
सदस्य:
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
- परामर्शदात्री समिति - मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सत्यमेव जयते

सांसद कार्यालय:
भाजपा जिला कार्यालय के सामने
जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)-491441
ई-मेल: me@abhisheksinghbjp.in
मोबाइल : 094790 94790
दूरभाष : 07744 221444
फैक्स : 07744 221441

क्रमांक 2568 दिनांक 8-10-15

प्रति,
आयुक्त
नगर पालिक निगम
राजनांदगांव

विषय:- **निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्प्रुवमेंट प्लान(SLIP) के संबंध मे।**

संदर्भ:- अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,नया रायपुर के पत्रक क्रमांक 9/सूडा/अमृत/2015/2578 दिनांक 06.10.2015

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकाय द्वारा सर्विस लेबल इम्प्रुवमेंट प्लान(SLIP) कुल रू.98.13करोड़ घटक में (1) पेयजल प्रदाय अंतर्गत रू.80.83 करोड़ (2) सेप्टेज मैनजमेंट रू. 12.00 करोड़ (3)हरित स्थल एवं पार्क रू.4.30 करोड़ (4) <u>सुधार कार्यक्रम</u> <u>**(REFORM)**</u> एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि रू.1.00 करोड़ तैयार कर अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है ।

अतः (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेबल इम्प्रुवमेंट प्लान(SLIP) की अनुशंसा की जाती है ।

240
08/10/15

कार्यालय नगर पालिक निगम
राजनांदगांव (छ.ग.)
शाखा
09 OCT 2015
अधीक्षक आयुक्त

भवदीय
(अभिषेक सिंह)

विष्णु देव साय
VISHNU DEO SAI

इस्पात एवं खान राज्य मंत्री
भारत सरकार
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
MINISTER OF STATE FOR STEEL AND MINES
GOVERNMENT OF INDIA
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI-110011

पत्र क्रमांक 752/एम.ओ.एस/इस्पात, खान/2015/ बगिया 08 अक्टूबर, 2015

प्रति,
माननीय श्री वैंकेया नायडु जी,
शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषयः- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का पत्र क्र. 1281/लो.क.वि./न.पा.नि./2015 रायगढ़ दिनांक 07.10.2015

——00——

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड रू. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. पेयजल प्रदाय - पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 96.44 करोड रू. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 10 ओवरहैड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट - अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड रू. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का

निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एमपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिषन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है। उपरोक्तानुसार अमृत मिशन अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ द्वारा प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

सादर,

भवदीय,

(विष्णुदेव साय) 3/10/2015

दिनेश कश्यप
संसद सदस्य (लोक सभा)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

22, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23782357
011-23782156

क्रमांक ...1567/2015

दिनांक 19/10/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
राज्य शहरी विकास अभिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा तैयार कार्ययोजना अमृत मिशन के तहत स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) के प्रावधानों तथा निकाय द्वारा सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुरूप जगदलपुर नगर पालिक निगम में पेयजल प्रदाय, सेप्टेज मैनेजमेंट, हरित स्थल एवं पार्क सहित सुधार कार्यक्रम एवं सुधार हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र जगदलपुर में कार्यों की आवश्यकता तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखकर, आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा प्रेषित कार्ययोजना स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा अनुशंसा करता हूं ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नः आयुक्त नगरपालिक निगम
जगदलपुर का पत्र मूलतः

(दिनेश कश्यप)

दिनेश कश्यप
[illegible]
[illegible]

क्रमांक 15 91/2015

[illegible]

दिनांक 12.10.2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य शहरी विकास अभिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:— नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा तैयार [illegible] अमृत मिशन [illegible] स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) के [illegible] द्वारा सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित [illegible] के अनुसार जगदलपुर नगर पालिक निगम में पेयजल प्रदाय, सेप्टेज मैनेजमेंट, [illegible] एवं पार्क [illegible] सुधार कार्यक्रम एवं सुधार हेतु [illegible] कुल [illegible] रूपये [illegible] प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

जगदलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र जगदलपुर में कार्यों की आवश्यकता तथा [illegible] को ध्यान में रखकर आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा [illegible] कार्ययोजना स्वीकृति हेतु एतद् द्वारा अनुशंसा करता हूं।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:— आयुक्त नगरपालिक निगम
जगदलपुर का पत्र मूलतः

(दिनेश कश्यप)

[illegible], पोस्ट भानपुरी, जिला बस्तर, (छ० ग०)
[illegible]: 07867-282606, कार्यालय: 07782-225210, फैक्स: 07782-231966

90 of 112

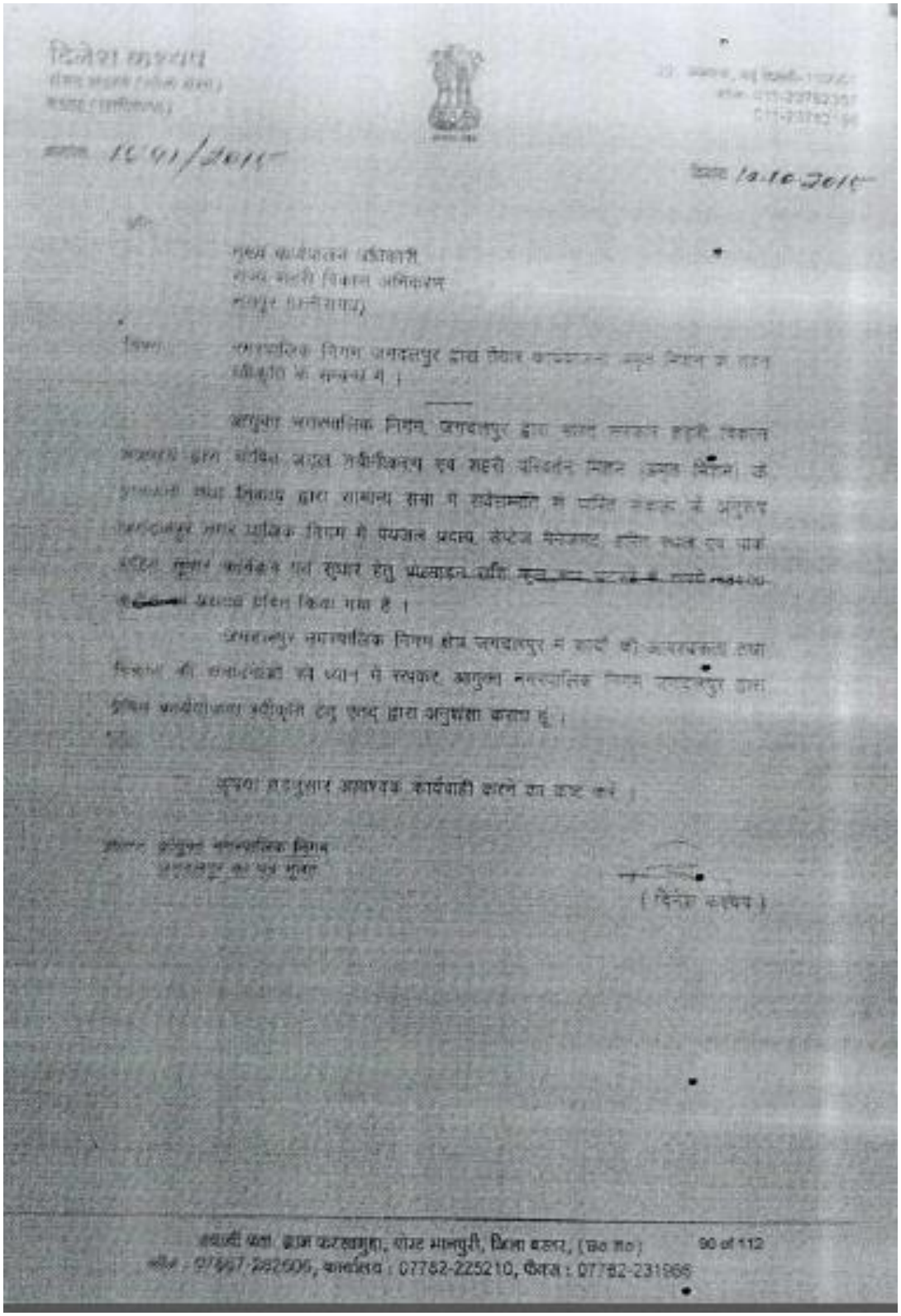

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नवीन मुख्यालय भवन,नगर पालिक निगम, गांधी चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं.-0771-2535760,90 फैक्स:0771-2227395,

क्रमांक/६२९/महापौर कार्यालय/न.पा.नि./15 रायपुर, दिनांक 09/10/2015

महापौर परिषद संकल्प

विषय – निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

—00—

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 21.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क.02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यो को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुमेंट प्लॉन (SLIP) तैयार किया गया है। मिशन हेतु केन्द्र/राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यो क्रमशः जल प्रदाय, सीवरेज मैनजमेंट में संर्वांग व्याप्ति (यूनिर्वसल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यो की कुल लागत राशि रू. 686.68 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) **पेय जल प्रदाय** :– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रू. 147.60 करोड़ रू. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम रायपुर में वर्तमान में जुडे 07 गांवों एवं छूटे स्थलों में नई पाईप लाईन, स्मार्ट मीटर एवं पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यो की मॉनिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

(2) **सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट** :– अंडर ग्राउंड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सैप्टेज के उपचार के लिए सैप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रू. 10.00 करोड़ का प्रावधान कियास गया है। नगर निगम, रायपुर में संपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु 04 जोन में डी.पी.आर तैयार किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण अंतर्गत केवल 02 जोन में डी.पी.आर के अनुसार राशि रू. 516.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(3) हरित स्थल एवं पार्क :– नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्राव्धान के साथ हरित स्थल एवं पार्को का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु राशि रू. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(4) सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :– मिशन अमृत के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले (REFORM) समय सीमा में पूर्ण किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 3.39करोड़ आगामी वर्षो में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षो के (SAAP) में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण (HPSC) द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलत घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी।

उपरोक्त कमांक 01 से 03 के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान 33 प्रतिशत तथा राज्यशासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 67 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय का अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएवं प्रकरण में राज्य का अंशदान 40 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 27 प्रतिशत मानकर (SLIP) का प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त प्रकरण को मेयर इन काउंसिल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुशंसा की जाती है।

महापौर
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09/10/15 अतिरिक्त प्रस्ताव क्र. 01

विषय :- निकाय में मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 22/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देश के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का सफलय सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा निर्देशो तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुये मिशन अवधि के लिये Service Level Improvement Plan (SLIP) तैयार किया गया है ।

मिशन हेतु SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों कमश : जल प्रदाय एवं सीवरेज /सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्यापि (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 278.71 करोड रुपये तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

01. पेयजल प्रदाय :- पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि रु. 245.53 करोड रुपये का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहो में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरुप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए खारुन जलाशय (खुटाघाट) के पास इन्टेक वेल कम पम्प हाउस का निर्माण कर 1200 एम एम व्यास (लंबाई 39.21 कि.मी.) के डी आई पाईप के माध्यम से पेयजल प्राप्त होगा । 77 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र दोमुहानी बैलेसिंग रिजर्वायर, क्लीयर वॉटर पंपिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग लम्बाई 35.12 कि.मी) का प्रावधान किया गया है । पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्य की मानिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है ।

02. सीवरेज :- सीवरेज की वर्तमान चलित योजना के पूर्ण होने पर 40000 घरों को सीवरेज की सुविधा प्राप्त होगी । वर्ष 2021 की डिमांड के अनुसार कुल 55000 घरों को कनेक्शन प्रदान किया जाना होगा, जिसके लिए 14.15 कि.मी. सीवरेज पाईप लाईन एवं 15000 प्रापर्टी चेम्बर कनेक्शन की आवश्यकता होगी । इस हेतु राशि रु. 16.32 करोड का प्रावधान किया गया है । कार्य पूर्ण करने की समय सीमा वर्ष 2017- 18 से वर्ष 2020-21 निर्धारित की गई ।

03. सेप्टेज मैनजमेंट :- अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिये निजी/ सार्वजनिक /सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिये सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये राशि रु. 5.47 करोड का प्रावधान किया गया है । इस घटक के अंतर्गत 02 नग सीवरेज सक्शन एवं जेटिंग मशीन 9000 लीटर क्षमता एवं 03 नग जेटिंग मशीन 500 लीटर क्षमता के साथ-साथ कुछ कॉलोनी जिनका ग्राउण्ड लेवल नीचे है अनुमानित आवासों की संख्या 2720 है, सीवरेज से जुडना संभव नही है, जिनमें सेप्टीक टैंक के स्थान पर बायोडायजेस्टर का प्रावधान किया गया है ।

04. <u>हरित स्थल एवं पार्क</u> :- नगर में प्रदूषण को रोकने के लिये हरियाली एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है । जिस हेतु राशि रु. 8.00 करोड की परियोजना सम्मिलित की गई है ।

05. **<u>सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि</u>** :- मिशन अमृत के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी । इस सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रु. 3.39 करोड़ आगामी तीन वर्षो में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी व्दारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटको में यह राशि व्यय की जावेगी ।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है । मिशन के दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किंतु राज्य सरकार शासन एवं नगरीय निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारुप तैयार किया गया है तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी व्दारा लिया जाना है । उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

आयुक्त

निर्णय :- सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सक्षम स्वीकृति हेतु यह प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है।

Kishor Rai महापौर, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)	निगम सचिव, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय ,नगर पालिक निगम भिलाई

प्रस्ताव क्रमांक–03 दिनांक 09.10.2015

विषय:– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 17/07/2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कव्हरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 256.41 करोड़ रू तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **पेयजल प्रदाय**– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 231.11 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 पति व्यक्ति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए रॉ वाटर पंप, सब स्टेशन, एनीकटवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (66 एमएलडी), रॉ वाटर राइजिंग, लगभग 110 किलोमीटर का वितरण प्रणाली, ओवरहेड टैंक, क्लीयर वाटर सम्प, क्लीयर वाटर पंपिंग मेन एवं पीएलसी स्काडा प्रणाली का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
2. <u>**सेप्टेज मैनेजमेंट**</u>– अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए प्रथम चरण में राशि 20.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सैप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, मल गाद प्रबंधन, परिवहन एवं शोधन तथा सीवर और सैप्टिक टैंको की सफाई एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत किया जाना सम्मिलित है।
3. <u>हरित स्थल एवं पार्क</u>– नगर में प्रदूषण को रोकने को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु 4.30 करोड़ रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है। इसके लिए प्रियदर्शनी परिसर एमुजमेंट पार्क, बोटानिकल गार्डन, ग्रीन बेल्ट, 48 नग हाचसिंग एरिया (एचएपी) एवं लीनियर पार्कों का निर्माण किया जाना सम्मिलित है।
4. <u>**सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि**</u>– मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

क्रमशः2/–

-2-

उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्पः— महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन का अंशदान 30 प्रतिशत एवं निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने तथा प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में सूचनार्थ रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया ।

सचिव
नगर पालिक निगम
भिलाई

महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 07.10.2015

प्रस्ताव कमांक :– 01

विषय :– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में ।

सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था । मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है ।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों कमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है । साथ ही रिफार्म लागू किए जाने का भी प्रावधान किया गया है । SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 67.73 करोड़ रू. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. पेयजल प्रदाय – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 47.43 करोड़ रू. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रचलित योजना द्वितीय फेरा जल आवर्धन के उपरांत शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने प्रावधानित किया गया है । वर्तमान में मानक अनुसार प्रतिव्यक्ति जल प्रदाय 135 ली. प्रतिदिवस के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है कवरेज 53.2 प्रतिशत से 100 प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है । योजना में कुल सात कार्य शामिल किया गया है । जिसमें विभिन्न वार्डों को सम्मिलित करते हुए जोन 01 से जोन 03 तक डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन स्थापित किया जाना है । ओ. एण्ड एम. के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु स्काडा वाल्व आपरेशन का प्रावधान किया गया है। पुलगांव वार्ड हेतु पृथक से फिल्टर प्लांट एवं ओवर हेड टैंक का प्रावधान किया गया है । साथ ही प्रत्येक कनेक्शन को मीटरिंग करने का प्रावधान किया गया है । प्रत्येक घर तक नये कनेक्शन हेतु पाईप लाईन विस्तार का प्रावधान किया गया है ।

2. सेप्टेज मैनेजमेंट – अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सेप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 15.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है । इस योजना में 30 एमएलडी का सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर कय किये जाने का प्रावधान है । नगर के समस्त सेप्टिक टैंकों को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचार किया जाना प्रावधानित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है जिस हेतु 4.30 करोड़ रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है ।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है । निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी । इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षो में प्रावधानित है । इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षो SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है । प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएसी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जावेगी ।

उपरोक्त क. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय का का अंशदान 50 प्रतिशत है । मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

मंतव्य :– प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत ।

सचिव
नगर पालिक निगम, दुर्ग

महापौर एवं अध्यक्ष
मेयर इन काउंसिल
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ.क्रमांक/ /नि.कार्या./2015 दुर्ग, दिनांक 07.10.2015

प्रतिलिपि:– आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।

सचिव,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

कार्यालय महापौर,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव (छ.ग.)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08/10/2015 में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि

विषय–1 निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) कियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में विचारार्थ।

संकल्प– विभागीय नस्ती का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिवेदन एवं संक्षेपिका अनुसार सामान्य सभा की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक 02 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा निर्देशा के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यो को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु (SLIP) में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यो के जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनजमेंट में सर्वांग व्यापि (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्को के विकास प्रावधान किया गया है। (SLIP) में सम्मिलित कार्यो की कुल लागत रू. 98.13 करोड़ तथा (SLIP) में सम्मिलित घटको का विवरण निम्नानुसार है :–

1. पेयजल प्रदाय:– पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 80.83 करोड का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। जिसमें नल संयोजन,स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवास गृह में अतर्राष्ट्रीय मानकों (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 04 एमएलडी क्षमता के 02 नग ओव्हर हेड टैक निर्माण कार्य,मोहारा जल संयंत्र गृह में 10 एम.एल.डी.से 27 एमएलडी प्लांट का इटरलिंकिग कार्य,विभिन्न वार्डो में 266 कि.मी.वितरण पाईप लाईन विस्तार कार्य का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं आपरेशन के कार्यो की मानिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर किये जाने का प्रावधान है।

2.सेप्टेज मैनजमेंट:– अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए राशि रू. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लाट का निर्माण तथा सक्शन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैक को सूचीबद्ध कर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट (STP) में उपचार किया जाना प्रस्तावित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क:– नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना है,जिस हेतु रू. 4.30 करोड़ की परियोजना सम्मिलित की गई है।

कमशः 2 पर...

// 2 //

4. **सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि:–** मिशन अमृत के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण कराने हेतु रू.1.00 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षो के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

कौंसिल की यह सभा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार कमांक 01 से 03 तक घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है एवं प्रकरण राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा इस निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर (SLIP) प्रारूप तैयार कर शासन को भेजे जाने की अनुशंसा करती है।

सही / –	सही / –
(देवेन्द्र सोनी)	(मधुसूदन यादव)
सचिव,महापौर परिषद	महापौर
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव	नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

पृ0क्र0158/सचिव / 15 राजनांदगांव दिनांक08/10/2015

प्रतिलिपि:–

1. अध्यक्ष,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ।
2. आयुक्त,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को सूचनार्थ।
3. प्र.अधिकारी लोककर्म, विभाग,नगर पालिक निगम,राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव 8-10-15
महापौर परिषद
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा छत्तीसगढ़

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 08.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक :- 176.

विषय :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 15.07.2015 में प्रस्ताव क्रमांक 18 में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि :-

मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड़ रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय संक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP का प्रारूप तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार मिशन अमृत के अन्तर्गत तैयार की गई SLIP महापौर परिषद, नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, कोरबा

मंतव्य :- प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।

सचिव
नगर पालिक निगम, कोरबा

Renu Agrawal
महापौर एवं अध्यक्ष
मेयर इन काउंसिल
नगर पालिक निगम, कोरबा

पृष्ठा.क्र./27762/सचिव कार्या./2015 कोरबा, दिनांक 08-10-2015

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, कोरबा

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 09.10.2015

प्रस्ताव क्रमांक – 01

विषय :– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.07.2015 में प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक 01 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के दिशा–निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए, मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवेरज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज प्राप्त करने हेतु) तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं पार्क के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यों की कुल लागत 111.74 करोड रू. तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. **पेयजल प्रदाय** – पेयजल प्रदाय हेतु कुल राशि 90.44 करोड रू. का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें नल संयोजन स्मार्ट मीटर सहित 100 प्रतिशत आवासगृहों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों (135 प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) के अनुरूप, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केलो नदी में एनीकट निर्माण, इंटेकवेल निर्माण, 10 ओव्हरहैड टैंक, 23.26 एमएलडी क्षमता का जलशोधन संयंत्र, मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर, वर्टीकल बॉटर पम्पिंग एवं वितरण प्रणाली (लगभग 183 कि.मी.) का प्रावधान किया गया है। पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण एवं ऑपरेशन के कार्यों की मानिटरिंग हेतु स्काडा साफ्टवेयर स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

2. **सेप्टेज मैनेजमेंट** – अण्डरग्राउण्ड प्रदूषण को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों में सृजित होने वाले सैप्टेज के उपचार के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए 10.00 करोड रू. का प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत 3 नग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण तथा समुचित सक्षन यूनिट/वैक्यूम इम्पटीयर क्रय किये जाने का प्रावधान है। नगर के समस्त सेप्टिक टैंक को सूचीबद्ध कर, निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सफाई कराकर एकत्रित सेप्टेज का परिवहन कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचार किया जाना सम्मिलित है।

3. हरित स्थल एवं पार्क – नगर में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाली एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल एवं पार्कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि 4.30 करोड रू. की परियोजना सम्मिलित की गई है।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशि – मिशन अमृत के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित है। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु 1.00 करोड रू. आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित है। इन सुधार कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों के SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्र. 01 से 03 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP कर प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

संकल्प :– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

महापौर
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय महापौर नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

मेयर–इन–कौसिंल की बैठक दिनांक 08.10.2015

निर्णय क्रमांक 09

विषय क्र.(09) निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :– नगर पालिक निगम के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 16.07.2015 के निर्णय क्रमांक 01 द्वारा भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित मिशन अमृत (अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार निकाय में लागू किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया है। मिशन अमृत के दिशा–निर्देशों तथा सामान्य सभा में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यों को सम्मिलित करते हुए मिशन अवधि के लिए सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) तैयार किया गया है।

मिशन हेतु प्रस्तुत SLIP में प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के कार्यो क्रमशः जल प्रदाय एवं सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट में सर्वांग व्याप्ति (यूनिवर्सल कवरेज) प्राप्त करने हेतु तथा प्रत्येक वर्ष हरित स्थल एवं उद्यान के विकास का प्रावधान किया गया है। SLIP में सम्मिलित कार्यो की कुल लागत रूपये 57.46 करोड़ तथा SLIP में सम्मिलित घटकों का विवरण निम्नानुसार है :–

पेयजल आपूर्ति – नगरीय क्षेत्र में मिशन के मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति के कार्य हेतु कुल राशि रूपये 46.16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों में स्मार्ट मीटर युक्त नल संयोजन, निर्धारित मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता 100 प्रतिशत स्तर तक सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु घुनघुट्टा डेम के आरबीसी जगदीशपुर में कनाल इंटेकवेल का निर्माण करते हुए 13.5 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया जाना, 04 नग उच्च स्तरीय जलागारों का निर्माण, पाईप लाईन विस्तार, जल शोधन संयंत्र हेतु पावर स्टेशन का निर्माण, पेयजल की गुणवत्ता एवं प्रबंधन कार्य हेतु स्काडा प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान SLIP में रखा गया है।

निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा, जिसके अनुसार मिशन अमृत के सम्मिलित घटकों के अन्तर्गत यह राशि आवंटित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं हरित स्थल तथा उद्यान निर्माण कार्य में व्यय होने वाली कुल लागत राशि का 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अंशदान राज्य शासन/नगरीय निकाय द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान मिशन अन्तर्गत है। मिशन के दिशा–निर्देशों के

अनुसार राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 30 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान 20 प्रतिशत मानकर SLIP प्रारूप तैयार किया गया है, तथापि राज्य शासन/निकाय अंशदान के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।

मिशन अमृत अन्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु उपरोक्तानुसार SLIP प्रारूप अनुमोदन एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– मिशन अमृत अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रस्तुत सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) राशि रूपये 57.46 करोड़ का अनुमोदन मेयर–इन–कौंसिल द्वारा सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है।

सचिव
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

महापौर/अध्यक्ष
मेयर–इन–कौंसिल
नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक 171 /सचिव/न.पा.नि./अम्बिकापुर दिनांक 09/10/2015

प्रतिलिपि :–

आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

sss

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ0ग0)
"मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 09.10.2015 में प्रस्तुत संक्षेपिका"

विषयः– निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के क्रियान्वयन हेतु सर्विस लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान (SLIP) के संबंध में।

4. सुधार कार्यक्रम (REFORM) एवं सुधार हेतु प्रोत्साहन राशिः– अमृत मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य एवं नगरीय निकाय स्तर पर कुल 54 अनिवार्य सुधार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। निकाय स्तर पर किये जाने वाले रिफार्म समय–सीमा में पूर्ण किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय की होगी। इन सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये– 1.00 करोड़ आगामी तीन वर्षों में प्रावधानित हैं। इन सुधार कार्यों को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने पर 10 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि आगामी वर्षों में SAAP में प्रदान किया जाना प्रावधानित हैं। प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर आगामी वर्ष व्यय हेतु दिशा–निर्देश का निर्धारण एचपीएससी द्वारा किया जावेगा। जिसके अनुसार अमृत मिशन के सम्मिलित घटकों में यह राशि व्यय की जायेगी।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक के घटकों में व्यय होने वाली कुल लागत राशि 50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान तथा राज्य शासन एवं नगरीय निकाय का अंशदान 50 प्रतिशत हैं। मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का न्युनतम अंशदान 20 प्रतिशत निर्धारित हैं किन्तु राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन एवं निकाय के अंशदान का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैं अतएव प्रकरण में राज्य का अंशदान 50 प्रतिशत तथा निकाय का अंशदान शुन्य प्रतिशत मानकर का प्रारूप तैयार किया गया हैं तथापि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया जाना हैं।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं सामान्य सभा की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
जगदलपुर